

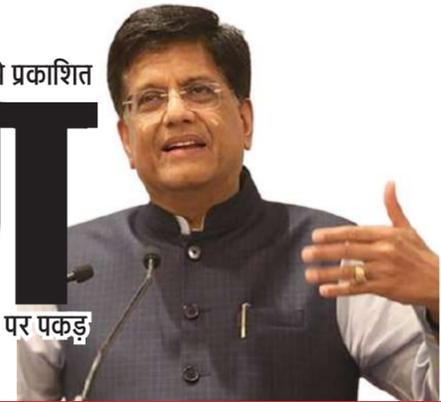
प्रातः किरण

हर खबर पर पकड़

f /Pratahkiran

t /Pratahkiran

wh /Pratahkiran



11 मैट्रिड ओपन : दानिल मेदवेदेव उलटफेर का शिकार, खचानोव जीते..... पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक हासिल..... 10

वर्ष : 13 | अंक : 346 | नई दिल्ली, गुरुवार, 04 मई, 2023 | वैशाख कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी, विक्रम संवत् 2080 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

कांग्रेस शांति व विकास की दुश्मन, आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टिकरण को बढ़ाती है : मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी
कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि विपक्षी पार्टी की पूरी राजनीति फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भारत के लोकतंत्र और विकास की वैश्विक स्तर पर सराहना और सम्मान किया जा रहा है तो वह दुनिया भर में जाकर देश को बदनाम कर रही है। कांग्रेस को शांति और विकास का दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री ने पार्टी पर भारत के रक्षा बलों का अपमान करने और उन्हें गाली देने का भी आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि जिस राज्य के लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वे सबसे पहले अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। तटीय कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की शहर में भारत माता की जय तथा बजरंग बली की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को अपने शाही परिवार के लिए नंबर-1 एटीएम बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टिकरण को बढ़ाती है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास, कृषि विकास के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा में नंबर-1 बने। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटक को दिल्ली में जो

उन्हां अपना करियर बनाना है और अपने मन का काम करना है तो यह कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, कर्नाटक में अगर अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं क्योंकि वह आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टिकरण को बढ़ाती है। उन्होंने साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों के बरी होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया कि घमाका करने वाले सारे के सारे दोषी, निर्दोष हो कर जेल से छूट गए। उन्होंने कहा,

तुष्टिकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कई मौकों पर रिवर्स गियर कांग्रेस कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि वह असांजिक लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर असांजिक लोगों का विरोध करते हैं तो रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही लोगों से चुनावी मदद लेती है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या ऐसी कांग्रेस को वे आने देंगे, कर्नाटक को बर्बाद होने देंगे और अपने भविष्य को तबाह होने देंगे? मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया लोकतंत्र और विकास को देखकर भारत को सम्मान दे रही है लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के हर कोने में भारत की जय-जयकार हो रही है क्योंकि लोगों ने अपने एक वोट की ताकत से दिल्ली में मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि देश में भी कर्नाटक की जय-जयकार हो, इसलिए इस राज्य में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। यह उल्लेख करते हुए कि भाजपा सरकार के तहत भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है जिसने हमें उपनिवेश बनाया था।

मौसम
अधिकतम तापमान 29.0°C
न्यूनतम तापमान 19.0°C

राजधानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार

हां	30%
नहीं	50%
कह नहीं सकते	10%

बाजार
सोना 62,145
चांदी 76,200

संसेक्स 61,655
निफ्टी 18,148

संक्षिप्त खबरें
देश में पिछले दस वर्षों में अंग प्रत्यारोपण के मामलों में तीन गुना बढ़ोतरी

भारत और मालदीव ने दो मित्र पड़ोसियों के रूप में रिश्तों को नया आकार दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन दिवसीय यात्रा में दीर्घकालिक साझेदारी को किया मजबूत

दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई

नई दिल्ली, एजेंसी
राजनाथ सिंह की तीन दिवसीय मालदीव यात्रा खत्म होने पर बुधवार को संयुक्त बयान जारी किया गया। मालदीवियन समकक्ष मारिया दीदी के निमंत्रण पर गए राजनाथ सिंह ने भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर चर्चा की और रक्षा एवं सुरक्षा



क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मालदीवियन समकक्ष रक्षा मंत्री मारिया दीदी के निमंत्रण पर 01 मई 2023 को माले पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर देते हुए

आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत को स्वीकारा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया और इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पड़ोसी देशों ने संयुक्त अभ्यास और दीदी और मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने के महत्व को भी नोट किया। दोनों मंत्री रक्षा व्यापार, क्षमता निर्माण और संयुक्त अभ्यास के क्षेत्रों सहित सहयोग के लिए अतिरिक्त रास्ते तलाशने पर सहमत

हूए। उन्होंने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से शिष्टाचार की आधारशिला रखी। कोस्ट गार्ड हार्बर का विकास और मरम्मत की सुविधा भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। यात्रा समाप्ति पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने गर्मजोशी पूर्ण और सौहार्दपूर्ण आतिथ्य की सराहना की। दोनों पक्षों ने अपने देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि वे भविष्य में बातचीत और सहयोग जारी रखने के लिए तत्पर हैं। इस यात्रा ने अपने-अपने देशों और क्षेत्र की सुरक्षा एवं समृद्धि को बढ़ाने के लिए दो मित्र पड़ोसियों के रिश्तों को नया आकार दिया।

सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री को कर्नाटक में कमीशन सरकार की लूट नहीं दिखी : प्रियंका

नई दिल्ली, एजेंसी
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए आक्षेप जताया कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री को कर्नाटक में 40 प्रतिशत कमीशन सरकार की लूट नजर क्यों नहीं आई। उन्होंने विजयपुर जिले में एक चुनावी सभा में यह सवाल भी किया कि विकास पुरूष (मोदी) अब भी ऐसा क्यों करते हैं कि कर्नाटक का विकास, उनका सपना है? प्रियंका गांधी ने कहा,

नाम 40 प्रतिशत कमीशन सरकार है। ठेकेदार संघ ने चिट्ठी लिखी, सर्वज्ञानी जी का कोई जवाब नहीं आया। ठेकेदार आत्महत्या करते हैं, लेकिन समस्या नहीं दिखती। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता इस चुनाव में इधर-उधर की बात करते हैं, लेकिन मुझे की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा विकास करना, अस्पताल बनाना, किसानों को राहत देना, महिलाओं को महंगाई से राहत देना, युवाओं को रोजगार देना है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, कर्नाटक में साढ़े तीन साल में मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं क्योंकि मौजूदा सरकार गलत तरीके से बनी। शुरू से ही इनकी नीयत सत्ता पाकर लूट मचाने और जनता की मुसीबतों को नजरअंदाज करने की रही है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की लूट की है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा कर्नाटक के नदिनी ब्रांड को खत्म करना चाहती है।

कांग्रेस शाही परिवार के लिए कर्नाटक को बनाना चाहती है 'एटीएम न वन': मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी
कर्नाटक के मुद्राविक्रय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय और बजरंग बली की जय के साथ की। पीएम ने कहा कि आज हम जिस सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी संतों की प्रेरणा है। 'कर्नाटक को नंबर एक बनाना चाहती है भाजपा' प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा, कर्नाटक को देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहती है और इसके बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाना चाहती है ताकि कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सके। वहीं कांग्रेस लोगों के रिटायरमेंट पर वोट मांग रही है, साथ ही भाजपा ने जो विकास किया है, उसे खत्म करने के नाम पर वोट मांग रही है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के वादे किए

जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ताजा बयान को कांग्रेस के उसी स्टैंड से जोड़कर देखा जा रहा है। गांधी परिवार पर बोला परोक्ष हमला प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि हम कर्नाटक को औद्योगिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक बनाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस, कर्नाटक को दिल्ली में उनके 'शाही परिवार' का नंबर एक एटीएम बनाना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में शांति की दुश्मन है, विकास की दुश्मन है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टिकरण को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए युवाओं से अपील की कि अगर उन्हें अपना करियर बनाना है और अपने मन का काम करना है तो उन्हें भाजपा को वोट देना चाहिए। पीएम ने कहा कि कर्नाटक में अगर अस्थिरता रही तो उनका भविष्य प्रभावित होगा। कांग्रेस की नीति 'बांटो और राज करो' वाली प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जहां भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वो सबसे पहले कांग्रेस को बाहर कर देते हैं, अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ सकती।



कर्नाटक की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध विध्वंस हिंदू परिषद (विहिप) की युवा शाखा बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई के कांग्रेस के चुनावी वादे का करारा जवाब देंगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसका यह रुख तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा कर भगवान हनुमान का अपमान किया है। विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए त्रिवेदी ने पूछा कि क्या कोई राज्य सरकार किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992 में आरएसएस के साथ ही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसे कुछ ही महीनों के भीतर हटाना पड़ा था क्योंकि सरकार इस मामले पर फैसला सुनाने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर सकी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार के पद छोड़ने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य ने कहा कि यह क्षेत्रीय पार्टी का आंतरिक मामला है लेकिन यह घटनाक्रम दर्शाता है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के भीतर किस प्रकार का समन्वय है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच हनफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्षिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल होगा।

हादिक आभार/अपील
मेरे समर्थन में निकाली गई जन विश्वास यात्रा में नगर के हर वर्ग व बिरादरी के लोगों ने हजारों की संख्या में भाग लेकर मेरा उत्साह बढ़ाया है। उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।
आपसे अपील करता हूँ कि 4 मई को कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाकर भारीमतों से विजयी बनाएं।
निवेदक - समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा एवं समस्त धनौरा नगरवासी

राजेश सैनी
भाजपा प्रत्याशी
निर्वातमान चेयर्मन नगर पालिका परिषद, धनौरा

संक्षिप्त समाचार

कार के नदी में गिरने से अल्मोड़ा के फार्मासिस्ट की मौत



गरमपानी (नैनीताल)। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर रात हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जा रही कार जड़मिला के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे शिप्रा नदी में जा गिरी। हादसे में फार्मासिस्ट की मौके पर मौत हो गई। खेरना चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सोमवार सुबह सात बजे जड़मिला के लोगों ने शिप्रा नदी में एक कार गिरने की सूचना खेरना चौकी पुलिस को दी। पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और कार में मौजूद शव को निकाला। खेरना चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया मुतक की पहचान कमल कुमार वर्मा (47) पुत्र वीएल वर्मा निवासी खर्जाचौ मोहल्ला अल्मोड़ा के रूप में हुई। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस ने बताया कि रविवार रात दस बजे तक उनकी बात कमल से हुई थी। उसके बाद उनका कमल से संपर्क नहीं हुआ। कमल गणाईगंगोली में फार्मासिस्ट थे। कमल की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

1783 इकाइयों से 14000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

रुद्रपुर, एजेंसी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) के तहत प्रदेशभर में लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। 13 जिलों में 1783 लघु इकाइयां स्थापित होंगी। प्रदेश में 14 हजार 264 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पीएमईजीपी योजना उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) की ओर से देशभर में वर्ष 2008 से संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रदेशभर के जिलों में पत्र भेजकर लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही 51 करोड़ 71 लाख रुपये की मार्जिन मनी दे दी गई है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि यूएस नगर में सबसे अधिक 145 इकाइयां स्थापित होंगी। इसके साथ ही अन्य जिलों के अपेक्षा यूएस नगर में 1160 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

वेतन की मांग पर अस्पताल के कर्मियों ने किया कार्यबहिष्कार

काशीपुर, एजेंसी। वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मियों ने चार घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान आकस्मिक सेवाएं भी बाधित रही। अस्पताल में सीएमएस पद पर तैनात डॉ. कैमारा राणा के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक रेंडिलोजॉसिस्ट डॉ. खेमपाल को सीएमएस बना दिया था। बीए शासन की अनुमति के सीएमएस बनाए जाने पर इस मामले में जांच बैठ गई। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमएस डॉ. खेमपाल से सभी वित्तीय अधिकार वापस ले लिए और उनको प्रभारी सीएमएस के तौर पर कार्य करने को कहा गया। वित्तीय अधिकार वापस लेने के कारण डॉक्टरों और स्टाफ का मार्च से वेतन जारी नहीं हो पाया। इसके विरोध में अस्पताल कर्मियों ने सोमवार से चार घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। बताया कि सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक तीन दिन तक रोजना कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इधर, कार्यबहिष्कार के चलते मरीज परेशान रहे। वहां पर डॉ. देवेश चौहान, डॉ. हरिश पंत, डॉ.अल्पना मिश्रा, डॉ. मनु पांडे, डॉ. शालिनी, डॉ. कमलजीत सिंह, डॉ. प्रियांका चौहान, रमेश चंद्र आर्य, विनोद भट्ट, दीनदयाल पंडे आदि थे। एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में सीएमएस की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य निदेशालय से पत्राचार किया गया है। उम्मीद है जल्दी ही नियुक्ति कर दी जाएगी।

महिला पुलिसकर्मी को दो वर्ष की सजा, 11 लाख का जुर्माना

रुद्रपुर, एजेंसी। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोप में महिला पुलिसकर्मी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 11,37,152 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांच साल पहले कार कि क्रिस्ट देने के लिए पुलिसकर्मी ने चेक का प्रयोग किया था। फरवरी 2018 में महेंद्र एंड महेंद्र फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात महिला पुलिस कर्मी पुष्पा भट्ट पर 9,37,152 रुपये का फर्जी चेक जमा करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी ने उनके बैंक से लोन पर कार ली है। क्रिस्ट के लिए फर्जी चेक जमा किए थे। प्रबंधक की तहरीर पर पुष्पा के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सीनियर सिविल जज श्रेता पांडेय के न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना था। अधिवक्ता आरोप खारज करने में तैनात। कि सभी सबूत और गवाह को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी पुष्पा भट्ट को दोषी करार दिया है। उन्हें दो वर्ष की कारावास और 11,37,152 रुपये का अर्धदंड की सजा सुनाई है।

गरीबों आवास का सपना पूरा करने की ओर बढ़े कदम

चंदन बंगारी, एजेंसी। छह सालों से कागजों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को धरातल पर उतारने की कसरत की जा रही है। शासन की ओर से कार्य शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने चयनित फर्म को 15 मई से पहले कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से प्रोजेक्ट में काम पड़ रहे 18 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए प्राधिकरण को स्टेट बैंक बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण जल्द ही शिविर लगाकर लाभार्थियों से आवेदन लेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत वर्ष 2017 में रुद्रपुर में गरीबों के लिए 1872 आवास बनाने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए मोदी मैदान में चार एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस जगह पर आवास निर्माण के लिए उडा और भारत सरकार की एजेंसी वेप्रॉक्स के बीच करार हुआ था। आवास निर्माण के साथ ही पार्क और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना भी थी। चार मंजिला भवन में बनने



वाले फ्लैट का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होना था लेकिन आवासों के मानचित्र सहित कई अड़ों लगने से योजना खिंचती चली गई। दो साल कोरोना की वजह से आवास की फाइल टंडे बस्ते में रही।

केंद्र की ओर से योजना में देरी पर कड़े रुख के बाद वर्ष 2022 में मोदी मैदान में निर्माण शुरू करने की कवायद हुई तो शासन स्तर पर मोदी मैदान को योजना के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसके बाद नए सिरे से

जमीन की तलाश शुरू हुई और जिला प्रशासन ने प्राधिकरण को बागबाला गांव में 15 एकड़ जमीन दे दी लेकिन प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई डीपीआर में लागत 130 करोड़ पहुंच गई। अनुमानित 112 करोड़ लागत में

18 करोड़ अधिक होने पर प्राधिकरण ने शासन से प्रतिपूर्ति की मांग की और मामले में पेच फंस गया था। लेकिन शासन की ओर से काफी इंतजार के बाद अब काम शुरू करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश मिल चुके हैं।
ये हैं योजना: लाभार्थी को सड़के तीन लाख रुपये का करना होगा भुगतान, सरकार की ओर से प्रोजेक्ट में ढाई लाख की दी जाएगी सब्सिडी, लाभार्थी को 5000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ करना होगा आवेदन, आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकरण लगाएगा शिविर, एचडीएफसी बैंक के माध्यम से जमा होगा शुल्क, आवेदक का नहीं होना चाहिए खुद का आवास, वार्षिक आय तीन लाख से नीचे वाले माने जाएंगे अर्ह, आवेदक का 2015 से पहले का निवासी होना अनिवार्य, परिवार की महिला ही कर सकेगी आवेदन, जंच के बाद आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे फ्लैट छह साल से कागजों में चल रही योजना से गरीबों को आवास का सपना लंबा हो चुका है।

देहरादून में आर्केडिया चाय बागान की 719 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी ट्विन सिटी, सरकार देगी सुविधा

देहरादून, एजेंसी। देहरादून के आर्केडिया चाय बागान में सरकार ट्विन सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। चाय बागान की 719.7 हेक्टेयर जमीन को इसके लिए चुना गया है। राजधानी में बढ़ते आबादी के बोझ को देखते हुए सरकार लगातार नए शहर बसाने पर काम कर रही है। इसके तहत देहरादून के डोईवाला और सहसपुर के छरबा में दो स्थान चिह्नित किए गए हैं। इसी कड़ी में आर्केडिया स्थित चाय बागान को भी नया शहर बसाने के लिए चुना गया है। जानकारी के मुताबिक आर्केडिया में सरकार ने न्यू देहरादून ट्विन सिटी बनाने की योजना के तहत यूएस की एजेंसी मैकेजी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया है। यहां नए शहर की जरूरतों के

हिसाब से सरकार ने संभावनाओं की तलाश की है। प्रथम चरण के सर्वे में काफी हद तक सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। अब आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके बाद निजी सहभागिता से यहां ट्विन सिटी बनाई जाएगी।
सरकार देगी सभी सुविधाएं जिस जमीन पर निजी सहभागिता से ट्विन सिटी बनेगी, वहां सरकार सभी सुविधाएं देगी। एक अत्याधुनिक शहर के हिसाब से यहां सड़क, बिजली, पानी से लेकर सभी जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध कराएगी। निजी निवेशक यहां टाउनशिप विकसित करेंगे, जिसकी बिक्री का एक हिस्सा सरकार के खाते में जाएगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं मिलेंगी: ट्विन सिटी में



अत्याधुनिक अस्पताल, स्कूल, कॉलेज से लेकर पार्क, जागिंग ट्रेक, साइकिलिंग ट्रेक आदि की सुविधा भी मिलेगी। सरकार एक पूरा ऐसा शहर बसा रही है, जिससे लोगों का आकर्षण यहां बने। वह जमीन खरीदें। घर बनाएं। अपना बिजनेस करें। इससे रोजगार भी मिलेगा।
2016 में चाय बागान की

जमीन पर हुआ था विवाद: वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की जमीन का विकल्प दिया था। ग्रीन फील्ड सिटी के तौर पर यहां स्मार्ट सिटी विकसित करने की सरकार की योजना पर भारी विरोध हुआ था। पर्यावरणविदों से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने इस पर विरोध

जताया था। उनका कहना था कि यहां नया शहर बसाने से हरियाली नष्ट हो जाएगी। यह चाय बागान देहरादून की पहचान है। चाय बागान मजदूरों के हितों और बागान की जमीन के संबंध में तमाम तरह के सुवाल उड़ाए गए थे। बड़ी संख्या में विरोध-प्रदर्शन हुए थे। हालांकि, सरकार ने ग्रीन फील्ड का प्रस्ताव जमा करवाया।

एजेंसी। फार्मासिस्ट पदों की बहाली समेत विभिन्न मांगों की अनेक संख्या के विरोध में सोमवार से जिले में फार्मासिस्ट ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो नौ मई को स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में ऋमिक अनशन पर बैठेंगे। डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सुबह आठ से 10 बजे तक सभी फार्मासिस्ट कार्य बहिष्कार पर रहे। उन्होंने कहा कि छह मई तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मानक लागू होने के बाद जिले में फार्मासिस्ट पदों की संख्या 66 से घटाकर 49 कर दी गई है। घटाए गए फार्मासिस्ट पदों की बहाली के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित आईपीएचएस संशोधन कमेटी गठित की रिपोर्ट भी लटकवा दी गई है।

मालरोड-चौबटिया सड़क झेल रही बदहाली का दंश



रानीखेत (अल्मोड़ा)। नगर के आंतरिक मोटर मार्गों की हालत खराब है। सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत रानीखेत-चौबटिया मोटर मार्ग मालरोड से लेकर झुला देवी तक बदहाल है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बारिश में यह गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं। जिस कारण दो पहिया वाहन चालकों और राहगीरों को खारीस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग को वीआईपी सड़क का दर्जा हासिल है। बड़े बड़े ऑटोमोबाइल और देशी विदेशी पर्यटकों इस सड़क से होते हुए चौबटिया उद्यान घूमने आते हैं। सड़क खराब होने से पर्यटक भी कड़वे अनुभव लेकर लौटते हैं। नगर के आंतरिक सड़कों की हालत भी खराब है।

अग्रजों के समय की जरूरी बाजार मोटर मार्ग बुरी तरह से खराब हो चुकी है। डेढ़ साल पहले इस मोटर मार्ग के गड्ढे पाटने का काम हुआ था लेकिन अब हालात पहले की तरह हैं। गांधी चौक से नैनीताल बैंक शाखा मोटर मार्ग फिर गड्ढों में तब्दील हो गई है। इन मोटर मार्गों के संरक्षण की जिम्मेदारी छत्रवर्नी परिषद को है। कनौसा कानवेट और आर्मी पब्लिक स्कूल को जोड़ने वाली सड़क कई स्थानों पर फिर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय के आवासीय भवनों के नीचे सड़क बदहाल है। रानीखेत से चौबटिया को जोड़ने वाला मोटर मार्ग मालरोड से लेकर झुलादेवी मंदिर तक खराब है। इस मार्ग पर बड़े-बड़े अधिकारियों के भवन हैं। प्रख्यात

उद्यान गार्डन भी इसी मार्ग पर स्थित है। साल भर उद्यान देखने के लिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन सड़क की हालत खराब होने के कारण उन्हें भी दिक्कतें होती हैं। इन दिनों बारिश हो रही है और सड़कों पर बने गड्ढे तालाब का रूप ले चुके हैं। रात्रि में इधर-उधर पहिया लोकर जाने वाले कई लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल तक हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की हालत सुधारने की मांग की है। इधर, लौनिवि प्रतीय खंड के महायक अभियंता केएस बिष्ट ने बताया कि माल रोड से झुलादेवी तक मोटर मार्ग एमएसएस के अंतर्गत है। लौनिवि के पास झुलादेवी से कुनैलाखेत मोटर मार्ग की जिम्मेदारी है।

समूह-ग की तीन भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे 184 अभ्यर्थी, पेपर लीक मामले में मिले थे नोटिस

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने चार भर्तियों में पेपर लीक करने वाले जिन 184 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उन्हें आगामी तीनों भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। नोटिस के जवाब आने के बाद आयोग इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार डिबार करेगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 अप्रैल को 184 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिन्हें पेपर लीक का आरोपी बताया गया था। इन सभी को आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि नोटिस का जवाब आने के बाद उन्हें आयोग अपनी सभी परीक्षाओं से डिबार कर देगा। अब चूक आयोग की पेपर लीक की वजह से रह गई परीक्षाएं दोबारा इसी महीने से शुरू होने जा रही हैं, लिहाजा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपियों को शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए परीक्षा कक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलेरिया का कहना है कि



निश्चित तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में नहीं शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब आने के बाद आयोग उन सभी को परीक्षाओं से डिबार कर देगा। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलेरिया ने बताया कि जो रह गई परीक्षाएं दोबारा कराई जा रही हैं, उनमें पूर्व के उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। कोई नया आवेदन नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल उन पूर्व उम्मीदवारों में से पेपर लीक के आरोपी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे।

दून के चाय बागान में ट्विन सिटी, पिथौरागढ़ में फिल्म सिटी, सहसपुर में बनेगी साइबर सिटी

देहरादून, एजेंसी। शहरों पर लगातार बढ़ रहे आबादी के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने प्रदेश में नए शहर बसाने के लिए 20 स्थानों का चयन किया गया था। इनमें से 10 का चयन किया गया।
दून के चाय बागान में ट्विन सिटी तो पिथौरागढ़ के निकट नैनी-सैणी में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। सरकार ने प्रदेश में ऐसे आठ स्थानों का चयन किया गया है, जहां नए शहर बसाए जाने हैं। निजी सहभागिता से ये शहर बसाए जाएंगे। शहरों पर लगातार बढ़ रहे आबादी के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने प्रदेश में नए शहर बसाने के लिए 20 स्थानों का चयन किया गया था। इनमें से 10 का चयन किया गया है। अब तक इनमें से आठ का चयन कर प्राथमिक सर्वेक्षण कराया जा चुका है। यूएस की एजेंसी मैकेजी की मदद से इन स्थानों पर नए शहर की सभी संभावनाओं को तलाश किया जा रहा



है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पराग फार्म के सिटी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से 1000 करोड़ मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी नए शहरों को बसाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में काम तेज कर दिया गया है।
इन दो जगहों पर दोबारा होगे सर्वे: रुद्रपुर शहर के पास 1577 हेक्टेयर निजी भूमि पर टाउनशिप विकसित की जानी है। इसके

रुद्रपुर/गदरपुर, एजेंसी। फार्मासिस्ट पदों की बहाली समेत विभिन्न मांगों की अनेक संख्या के विरोध में सोमवार से जिले में फार्मासिस्ट ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो नौ मई को स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में ऋमिक अनशन पर बैठेंगे। डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सुबह आठ से 10 बजे तक सभी फार्मासिस्ट कार्य बहिष्कार पर रहे। उन्होंने कहा कि छह मई तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मानक लागू होने के बाद जिले में फार्मासिस्ट पदों की संख्या 66 से घटाकर 49 कर दी गई है। घटाए गए फार्मासिस्ट पदों की बहाली के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित आईपीएचएस संशोधन कमेटी गठित की रिपोर्ट भी लटकवा दी गई है।

जिले में दो घंटे कार्य बहिष्कार पर रहे फार्मासिस्ट

रुद्रपुर/काशीपुर/जसपुर/बाजपुर, एजेंसी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर जिलेभर के राशन विक्रेताओं ने बेमियादी खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार शुरू कर दिया है। राशन विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं को राशन नहीं बांटा। उन्होंने मांगें पूरी होने पर ही आंदोलन खत्म करने की चेतावनी दी है। सोमवार को तीन सूत्री मांगों के लिए विक्रेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। शासन की ओर से मांगों को लेकर बेरुखी के चलते उन्होंने एसएमआई गोदामों से खाद्यान्न नहीं उठाया। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र बांग ने बताया कि कार्यबहिष्कार में 642 राशन विक्रेता शामिल हैं। इधर, डीएसओ विपिन कुमार ने बताया कि गल्ल विक्रेताओं की लाभांश खातों में डालने और पीएमजीएवाई का सात महीने का लाभांश खातों में जमा करने की मांग को पूरा किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मानदेय का मामला शासन स्तर पर है। काशीपुर में संगठन के अध्यक्ष विनोद कुमार सारस्वत व प्रदेश उपाध्यक्ष सार्थक अग्रवाल ने बताया जब उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता कार्यबहिष्कार करेंगे। वहां पर माजिद अली, हरिश पांडे, अनिल सिंघानी, संजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इधर, जसपुर में आदर्श राशनियर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने डीएसओ को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद चंद तिवारी दिया। वहां पर देवेन्द्र सिंह चौहान, अनुराग कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, तनवीर हसन, मो. मुस्तकीम, शिवम विरन्नी आदि शामिल रहे। वहीं, बाजपुर में गल्ल विक्रेताओं ने कहा जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता कार्यबहिष्कार जारी रहेगा। यहां पर अध्यक्ष अजय कालरा, रविशंकर गौयल, मदन मोहन आजाद, अकरम आदि मौजूद रहे। 2023 के जनवरी महीने से आज तक का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मासिक लाभांश शीघ्र विक्रेताओं के खातों में जमा किया जाए। पीएमजीएवाई का पिछले सात महीने का लाभांश का पूर्ण भुगतान बैंक खातों में शीघ्र जमा किया जाए। उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की तरह सरकारी गल्ल विक्रेताओं को लाभांश के अतिरिक्त मानदेय महीने में दिया

दिल्ली के 360 गांवों ने खिलाड़ियों को दिया समर्थन : गोपाल राय

• इस्पाक की मांग कर रहे इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है और आज इनकी जाति पूछी जा रही है- गोपाल राय

• यह लड़ाई देश के खिलाड़ियों और बहन-बेटियों के मान-सम्मान की है, दिल्ली के भाजापा खासद भी जंतर मंतर आकर साथ दें- गोपाल राय



नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को जंतर-मंतर पर जाकर न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन किया। ये प्रतिनिधि आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय के नेतृत्व में यहां पहुंचे थे। इसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, कई विधायक व पार्षद समेत गणमान्य लोग शामिल थे। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार इस गलतफहमी में है कि खिलाड़ी धरना खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली के लोग इनके साथ हैं और इनकी हिम्मत नहीं टूटने देंगे। उन्होंने दिल्ली के भाजपा सांसदों को भी खिलाड़ियों का साथ देने के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह तथ्य क्विया गया है कि 7 मई को फिर गांवों के लोग जंतर-मंतर पर जुटेंगे और महापंचायत कर आंदोलन की आगे की रणनीति बनाएंगे।

संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जंतर मंतर पर धरनातर खिलाड़ियों के समर्थन में आए दिल्ली के 360 गांवों से आए प्रतिनिधियों, पार्षदों व विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीत कर देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को पिछले 10 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। देश की शान हमारी बहनें गर्मी और बारिश में भी आंदोलन करने की मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, देश के प्रधानमंत्री के पास फुसंत नहीं कि वे इन खिलाड़ियों को बुलाकर इनसे बात कर सकें। कल भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने टवीट किया कि आप के नेता इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर उनके अंदर समाज और बहन-बेटियों की इज्जत को लेकर चिंता है तो वो भी

आकर हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठें और खिलाड़ियों का समर्थन करें। इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा फहराया है और आज इन्होंने इनकी जाति पूछी जा रही है। लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी जाति से ऊपर है। एक खिलाड़ी को तैयार करने में एक परिवार अपना सबकुछ दांव पर लगा देता है। मां-बाप अपना पेट काटकर, अपना सब कुछ न्यौछार कर अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाने के लिए भेजता है और ये खिलाड़ियों की जात पूछ रहे हैं। खिलाड़ियों की एक ही जात है, ये हिंदुस्तानी हैं। जो भारत के लोगों की जाति है, वही हमारे खिलाड़ियों की जाति है। जब ये खिलाड़ी तिरंगे के सम्मान के लिए बाहर जाते हैं तो उसके साथ सभी जातियों की दुआएं और आशीर्वाद भी जाता है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को समर्थन

देने के लिए दिल्ली के नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, मटियाला, छतरपुर, बिजवासन समेत 360 गांवों के प्रतिनिधि आए हैं। ये एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि अगर भाजपा की सरकार यह सोचती है कि इन खिलाड़ियों को हम ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे और एक दिन मजबूर होकर ये जंतर मंतर छोड़कर चले जाएंगे तो आप गलतफहमी में है। केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जैसे किसान नहीं गए, क्योंकि मजबूर केंद्र को होना पड़ा और तीनों कानून वापस लेने पड़े। सरकार जितना इन खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने की कोशिश करेगी, उतना देश से समर्थन का जमावड़ा जंतर मंतर पर लगता रहेगा। अगर केंद्र सरकार इनकी हिम्मत तोड़ना चाहती है तो पूरी दिल्ली के गांव इनकी हिम्मत जोड़ना चाहते हैं। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने गांव के प्रतिनिधियों के सामने प्रस्ताव रखते हुए एक पाठ दिया कि हमारे देश को बेटियां यहां आंदोलन कर रही हैं। इनके समर्थन में दिल्ली के सभी गांवों में पंचायत बुलाई जाए। पंचायत में सभी बिरादरी के लोगों को बुलाकर खिलाड़ियों के समर्थन पर चर्चा की जाए कि क्या हमें इनका साथ देना चाहिए या नहीं? क्या हमें न्याय का साथ देना चाहिए या नहीं? दूसरा, 4, 5, और 6 मई को दिल्ली के सभी गांव अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत करें और 7 मई को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाए।

खिलाड़ियों के समर्थन में सभी गांव के लोग, प्रतिनिधि, पार्षद व विधायक 7 मई की सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर आए, ताकि सभी गांवों की महापंचायत की जा सके। सरकार सभी खिलाड़ियों की मांग पर जिम्मेदारी के साथ चर्चा करे और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 7 मई को महापंचायत के साथ इस आंदोलन की अगली रणनीति और अगले चरण की घोषणा की जाएगी। आप दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के सांसदों से पूछा कि जो हर बार जंतर मंतर पर भागकर आया करते थे वे अब इन खिलाड़ियों की गृहार सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लड़ाई देश के खिलाड़ियों व बहन-बेटियों के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों को 7 मई की महापंचायत में आने का निमंत्रण देता हूँ, ताकि सब मिलकर चर्चा कर सकें कि हमें खिलाड़ियों का साथ देना है या नहीं। 7 मई की महापंचायत किसी एक पार्टी की नहीं है, कोई भी पार्टी या संगठन इसमें शामिल हो सकता है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जंतर मंतर पर दिल्ली के करीब 360 गांवों से प्रतिनिधि आए हैं। मेडल जीतने वाली हमारी बेटियां इन्हीं गांवों से आती हैं। इन्हीं गांवों से बाहर निकलकर हमारी बेटियां कोचिंग और कैम्प में ट्रेनिंग लेने के बाद देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। हमारे इन्हीं गांव के लोग अपनी बेटियों को देश का नाम ऊंचा करने के लिए भेजते हैं।

अंबेडकर की विरासत पर आयोजन

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



अंबेडकर स्टीडी सर्कल, राजधानी कॉलेज के तत्वावधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान एवं कवि सम्मेलन का आयोजन दिनांक 2 मई 2023 को किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय डॉक्टर अंबेडकर की बढ़ती हुई प्रासंगिकता रहा। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश गिरि ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को निरंतर और हर रोज समाज में फैलाए जाने की आवश्यकता है। राजधानी कॉलेज के ब्रह्म प्रो. सुमन कुमार ने समाज के प्रत्येक परिवार में अंबेडकर को खोजने पर जोर दिया। प्रो. गीता सहारे ने कहा बाबा साहेब की विरासत के कारण हमें आज बोलने का अधिकार प्राप्त है। यह बाबा साहेब का ही सपना है कि समाज को बदलने के लिए इस विरासत को वर्तमान पीढ़ी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर प्रमोद मेहरा ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बाबा साहेब को शिक्षाविद के रूप में जानने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा औरों को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। प्रो.

कविगणों में अनिता भारतीय ने विचारवाली की बीवी, रुखसाना का घर, संतोष पटेल ने मैं अंबेडकर हूँ, जज्वात तुम्हारे भी, मेरे सपनों में चुपके से आया करो, आलोक कुमार मिश्रा ने दिल्ली के आगे दिल्ली, सुकामना, हीरा मीणा ने कौन हैं वे, मैं बाजुकी हूँ एवं प्रो. जितेंद्र श्रीवास्तव नेरामदुनारी, सोन चिरइयां इत्यादि कविताओं से दर्शकों को बांधे रखा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते समय संयोजक महे सिंह बेनीवाल ने अपनी कविता तत्वीर सुनाई। अंबेडकर स्टीडी सर्कल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के विचारक का संचालन डॉ. सर्मिता मोहंती एवं कविता सत्र का छत्र अभिषेक तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रो. सुशील दत्त, प्रो.पंकज गुप्त डॉ. गिरिज बैक्वा, डॉ. वेदमित्र शुक्ल, प्रो.राजेन्द्र कुमार, डॉ उमेश कुमार, डॉ बंटी कुमार, डॉ मनोहर सिंह, डॉ शोफली राठौर, डॉ अदिति शर्मा, डॉ अरुण लाल, डॉ आनंद कुमार, डॉ संजीव शर्मा, डॉ संतोष यादव, डॉ नवल किशोर, डॉ राजवीर सिंह, डॉ देवकुमार, डॉ प्लावी सेन, डॉ चंदन भारती, डॉ. अमित कुमार , डॉ. अंकित अभिषेक, डॉ सतीश कुमार, एवं डॉ. सर्वेश कुमार आदि की गौरमाम्य उपस्थिति के साथ-साथ भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

रवीन्द्र कुमार सहरावत ने दुनिया या समाज को बेहतर बनाने के लिए हाशिए के लोगों की सेवा करने को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा- बाबा साहेब के विचारों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। डॉ. सुनील बाबू ने बाबा साहेब को न सिर्फ राष्ट्र का बल्कि समूचे विश्व का मसीहा बताया। व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात् छात्रों के साथ प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र (कवि सम्मेलन) में रविन्द्र कुमार दास ने अपनी कविता मगध की जनता में कोई असंतोष नहीं है एवं कौन है त्रिजटा , डॉ. जसवीर त्यागी ने अपनी कविता जिनके घर नहीं होते, एक पुष्प की ताकत एवं डॉ. धीरज कुमार यादव ने अपनी कविता पुष्प के मध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इस सत्र के अतिथि

आरोप पत्र में संजय सिंह का नाम गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर डाला गया: आप

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र में पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नाम का उल्लेख किया जाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का सोचा-समझा प्रयास है।

वहीं ने कहा कि सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है और उनसे आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रवर्तन विभाग (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी मांगी है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में आप नेता का चार बार नाम आया है, जिसमें से एक संदर्भ गलत है और अजनाने में टाइप

आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वह ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करेगे क्योंकि उन्होंने आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया और बाद में मीडिया को बताया कि संजय सिंह भी इस मगनद्वंद्व घोटाले में शामिल थे। भारद्वाज ने कहा कि ईडी विपक्षी दलों से डरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने संजय सिंह से माफ़ी मांगी है। भारद्वाज ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ जब ईडी के निदेशक को किसी से माफ़ी मांगनी पड़ी। एक तरह से केंद्र सरकार को संजय सिंह और आप से माफ़ी मांगनी पड़ी है। उन्होंने पूछा कि यहगलत कैसे हुई। भारद्वाज ने कहा, उन्होंने कहा कि गलती से नाम का उल्लेख हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? भाजपा के किसी सांसद का नाम तो गलती से नहीं आया। प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर यह डाला गया।

पति ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर में बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित ने खुद के पेट में चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान शोर-शराबा सुनकर पड़ोसियों ने मामलों को सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने पत्नी नेता (32) को मृत घोषित कर दिया। जबकि आरोपित पति विक्की की हालत नाजुक बनी हुई है। क्राइम टीम के अलावा एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए हैं और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की छानबीन कर रही है।

पुलिस के मुताबिक बिहार की रहने वाली नेहा अपने परिवार के साथ नजफगढ़ के गोपाल नगर स्थित किराए के मकान में रहती थी। इसके परिवार में पति विक्की के अलावा दो बेटियां हैं। विक्की पिछले तीन-चार महीने बेरोजगार था। वहीं नेहा घरेलू सहायिका का काम कर परिवार को चला रही थी। घर की आर्थिक परिस्थिति को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। बुधवार सुबह करीब 9.00 बजे किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान गुस्से में आरोपित ने घर में रखे बड़े चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। इसके बाद भी पत्नी के पेट पर चाकू के कई वार किए। इसके बाद आरोपित ने अपने पेट में भी चाकू घोंप लिया। वारदात के समय नेहा की पांच साल की बेटी स्कूल गई थी। वहीं बड़ी बेटी घर पर ही मौजूद थी। आरोपित ने बेटी के सामने ही नेहा की हत्या की। घटना के बाद से बेटी दहशत में है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुए चाकू को बरामद कर लिया है। नेहा के परिवार को खबर देने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि परिवार इसी संपाह इस मकान में आया था। इससे पूर्व कुछ दूरी पर दूसरे मकान में रहता था।

अदालत ने केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड से ली गई 123 गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। इस साल की शुरूआत में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने दो सस्वर्यी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था, जिसमें फर्जंद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। भूमि एवं विकास कार्यालय के उप-अधिकारी ने आठ फरवरी को बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को लिखे एक पत्र में समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से अलग करने के निर्णय की जानकारी दी थी हाल के एक आदेश में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने इन 123 संपत्तियों को गैर-सूचीबद्ध

करने के केंद्र के कदम के खिलाफ बोर्ड को याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रोक लगाने की अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदनों को दलीलें पूरा होने के बाद निपटार के लिए लंबित रखा जाएगा। केंद्र ने कहा कि फिलहाल वह केवल संपत्तियों के भौतिक निरीक्षण का ही अनुरोध कर रहा है, जिसके बाद सभी संबंधित सामग्री को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा, इसके मद्देनजर, मौजूदा याचिका में एक अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण,

प्रतिवादी अपने आठ फरवरी के पत्र के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण की कार्यवाही कर सकता है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा 1911 से जुड़ा है और इस मामले को थोड़े विस्तार से सुना गया है। अदालत ने कहा कि ऐसे में केंद्र से एक विस्तृत जवाबी हलफनामा मांगना और साथ ही याचिकाकर्ता बोर्ड के पक्ष को सुनना उचित होगा। अदालत ने मामलों की आगामी सुनवाई दो नवंबर के लिए सूचीबद्ध की।

देश के सामने केंद्र सरकार और ईडी हुई एक्सपोज, एक फर्जी घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम डालने पर ईडी ने मांगी माफ़ी: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



केंद्र सरकार और उसकी ईडी बुधवार को पूरी तरह एक्सपोज हो गई। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बदनाम करने के लिए उनका नाम एक फर्जी घोटाले की चार्जशीट में डालने पर ईडी को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी है। ईडी द्वारा माफ़ी मांगने पर आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आश्चर्य जताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। यह केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। उन्हें यह शोभा नहीं देता है। वही, वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर माफ़ी मांगी है कि गलती से चार्जशीट में सांसद संजय सिंह का नाम आ गया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

भारद्वाज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि आज हमारे देश में दो एजेंसियां-ईडी और सीबीआई डराने-धमकाने, किसी को परेशान करने, टॉर्चर व उत्पीड़ित करने और किसी को इज्जत को पूरी तरह से नालाम करने की पर्यायवाची बन गई हैं। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोषणा की थी कि वे केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेसन का मुकदमा दायर करेंगे। क्योंकि ईडी ने गलत व झूठे तरीके से संजय सिंह का

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



चौकी चर्च मिशन गेट पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मो. मुनीर निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी खास और आरिफ निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी खास, है। पुलिस ने इनके पास से थाना फर्श बाजार क्षेत्र से चोरी हुई बाइक, एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामलों की जांच कर रही है। उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 01 मई को रात के समय चांदनी चौक, कच्चा घासी राम में पेट्रोलिंग स्टॉप थाना अघ्राक्ष विजेंद्र राणा और चौकी इंचार्ज एसआई रणविजय की देखरेख में एएसआई देवेंद्र, एचसी अनिल व

जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया और एक अन्य जिंदा कारतूस अन्य के कब्जे में बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी कच्ची घासी राम में कारोबारियों पर नजर रखते थे और मौका पाकर रास्ते में लूट, छिनटाई और पैसे लूट लेते थे और अपनी गलतफ़ेद पर पैसे भी खर्च करते हैं।

आज का दिन केंद्र सरकार और ईडी के लिए बहुत शर्मसार करने वाला- सौरभ भारद्वाज

आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज केंद्र सरकार और ईडी के लिए बहुत शर्मसार करने वाला दिन है कि ईडी ने लिखित में माफ़ी मांगकर अपनी गलती सुधारी है। जिस चार्जशीट में संजय सिंह का नाम डाला था, उसके लिए उन्होंने ईडी को लौगल नोटिस डालकर धमकी दी। आज उस कोर्ट में ईडी ने एप्लीकेशन डालकर कहा कि गलती हो गई और संजय सिंह का नाम हटा दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सबक है। यह इस षडयंत्र का पदापर्श करता है कि इनके दिमाग में भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम घूमते रहते हैं कि किस नेता को कैसे फर्जी मामले में फंसाया जाए। अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए। आज पूरी केंद्र सरकार पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से षडयंत्र करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को झूठे और फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे है, उसका सच पूरे देश के सामने आ गया है, यह बहुत शर्म की बात है। वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने टवीट कर कहा, क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें वे शोभा नहीं देता।

आबकारी नीति मामला: उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

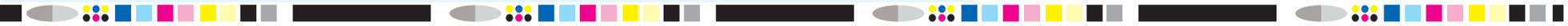
नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता



दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से बृहस्पतिवार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी दिन अदालत में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की पत्नी की चिकित्सकीय स्थिति पर तत्काल ध्यान दिव जाने की जरूरत

है। साथ ही वकील ने अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि बृहस्पतिवार को रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं होगा। इसपर अदालत ने सीबीआई के वकील से कोशिश करने और बृहस्पतिवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा ताकि अर्जी पर

नियमित जमानत याचिका के साथ ही सुनवाई की जा सके। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित प्रष्टाकार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 31 मार्च को निचली अदालत ने इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश को सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई।



पुराने एजेंडे का घोषणापत्र

जनसंघ के दौर से तीन बुनियादी मुद्दे रहे हैं-अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता। पार्टी का रूपांतरण भाजपा के तौर पर हुआ, तो यह पुराना एजेंडा बरकरार रखा गया। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 संसद के जरिए समाप्त किया जा चुका है। हालांकि यह मामला अभी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। अब भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने पर आमादा है। यानी एक देश, एक कानून। कर्नाटक के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे रखा गया है। भाजपा ने उत्तराखंड, हिमाचल, उप्र, मप्र, गुजरात और असम आदि राज्यों में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में या तो कमेटी का गठन किया गया है अथवा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। हिमाचल को छोड़ कर शेष राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। हरियाणा के गुर्गमंडी अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर आश्वासन दिया है, तो महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, इसी संदर्भ में याग करते हुए, पत्र लिखा है। दरअसल जब-जब चुनाव आते हैं, तो समान नागरिक संहिता का आश्वासन गरमाने लगता है।

अलबता केंद्र में बीते 9 साल से भाजपा की मोदी सरकार कार्यरत है, लेकिन न तो विधि आयोग से यह मुद्दा पारित कराया गया, न आयोग की कोई अनुशंसा है और न ही राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है। वैसे यह मामला समवर्ती सूची में है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसे लागू कर सकती हैं। सर्वोच्च अदालत भी इसे लागू करने की बात कह चुकी है। अब एक टीवी साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि हम बिल ला सकते हैं। बहरहाल उसके लिए संसद सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव तक समान नागरिक संहिता को गरमागरम रखेगी। फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा। कर्नाटक में समान नागरिक संहिता के साथ-साथ भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की भी घोषणा की है।

आश्चर्य है कि दक्षिण के किसी भी राज्य का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, तो अवैध घुसपैठियों या प्रवासियों की पहचान के लिए कर्नाटक में एनआरसी लागू करने की घोषणा क्यों की गई है? यह बेहद विवादास्पद और मुसलमानों में भय पैदा करने वाली घोषणा है। असम के स्तर पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। उसमें कई विरोधाभास और विरसंगितियां सामने आई थीं। मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। समान नागरिक संहिता और एनआरसी से जरिए और अन्य घोषणाओं के तहत भाजपा ने कर्नाटक में भी हिन्दुत्व पर फोकस रखा है। पार्टी ने 2500 करोड़ रुपये से 5 सर्किट बनाने का वायदा किया है-परशुराम के 3 सर्किट, गंगापुरा सर्किट और कावेरी सर्किट। इनके अलावा, गोवध प्रतिबंध कानून और जबरन धर्मांतरण कानून को अधिक सख्त बनाने की भी घोषणा की गई है। भाजपा ने मंदिर अर्थव्यवस्था की सोच के तहत मंदिरवादी लोगों की अपेक्षाओं और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मंदिर पुराणों में या उनके बाहर मुसलमानों के कारोबार और त्योहारों के दौरान दुकानें स्थापित करने पर हानि लगाई जाए, कर्नाटक के मंदिरवादी हिन्दुओं की यह मांग तो पूरी तरह ह्र्असंवैधानिकहह है। अभी हमने मुफ्तखरी को रेवडिां पर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उस चुनाव में रेवडिां बांटेने की घोषणाएं की हैं। बैराक वे जन-कल्याण का दावा करें, लेकिन वे रेवडिां ही हैं। दक्षिण के राज्यों की तुलना में कर्नाटक में मानव विकास सूचकांक-स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि-पिछड़ा हुआ है। उसके बावजूद रेवडिां की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभाओं में या अन्य मंचों पर इस मुद्दे पर चिंता लगातार व्यक्त करते रहे हैं। उनका आकलन है कि राज्यों पर जिस तरह कर्ज के बोझ बढ़ रहे हैं, उससे देश की समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन रेवडिां बांटी जा रही हैं अथवा हिन्दुत्व, मुस्लिम आरक्षण, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, स्कूटी, साइकिल, नकदी, किसानों के लिए 30, 000 करोड़ रुपए का फंड आदि के सुनहरी जुमले परसे जा रहे हैं। यह कैसी है सियासतद्दु? सभी दल मुप्त की रेवडिां के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। विकास का यह कोई उचित मॉडल नहीं है।

बजरंगी पालटिक्स के अक्स

राकेश अघल

मुझे नहीं पता कि हमारे रामसेवक बजरंगबली ने कभी कोई संगठन या दल बनाया था। उनके जमाने में दलों के पंजीयन की कोई व्यवस्था थी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली और बजरंग दल को एक कर दिया है। कांग्रेस ने बजरंगदल पर पाबंदी का वादा कर भाजपा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि भाजपा की सारी राजनीति का आधार ये हवा-हवाई संगत ही हैं। देश का दुर्भाग्य है कि यहां की राजनीति लगातार प्रगतिशील होने के बजाय प्रतिगामी होती जा रही है। देश की राजनीति में 1980 में जन्मी भाजपा ने पहले भगवान राम को राजनीति के लिए औजार बनाया और आज जब राम के नाम पर वोट मिलना बंद होने वाले हैं तब उनके सेवक हनुमान को अपना औजार बना लिया है। देश के प्रधानमंत्री जी तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हनुमान जी को जेल में बंद कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मै दिल से उम्मान करता हूँ क्योंकि जितने विनोद की बातें व करते हैं अब तक के किसी प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने नहीं सुनी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब खुद इस विनोद को महाविनोद में बदलते हैं तो मुझे हैरानी होती है। बकीोल कांग्रेस इस देश की महाभ्रष्ट और देशद्रोही है, इसलिए इसे देश से समूल नष्ट कर देना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो जरूरू ऐसा कीजिए। लेकिन ऐसा करने के लिए राम या हनुमान का इस्तेमाल बिल्कूल मत कीजिये। ये इन दोनों महान प्रतीकों के साथ अन्याय है। उसके बावजूद रेवडिां की राजनीति की जा रही है। 30 अप्रैल को, प्रसारित किये गये इस शतकीय एपिसोड को देश विदेश में अधिक लेखकों ने अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये युद्धस्तरीय तैयारियां की गयी थीं। देशभर के करीब 4 लाख केंद्रों में सामूहिक रूप से सुने गये इस कार्यक्रम को देश की अनेक संस्थाएं अधिक जनता के बीच आने के लिये देश भर की भाजपाईं सरकारों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, सांसदों, विधायकों आदि सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस प्रसारण के कई दिन पहलू से ही देश भर के सैकड़ों भाजपाईं महत्वियों, नेताओं व सत्ता समर्थक अनेक लेखकों ने कार्यक्रम की तारीफ संबंधी आलेख देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा कर

विचारमंथन

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस: एक बहुमूल्य रत्न!

इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाों और सहकारी समितियों ने किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख ऑनलाइन लेनदेन के जरिए दो लाख करोड़ रुपये (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाों और सहकारी समितियों ने किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख ऑनलाइन लेनदेन के जरिए दो लाख करोड़ रुपये (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की। यह समावेशी विकास, पारदर्शिता, दक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्धता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। जीईएम सही अर्थों में एक रत्न है। इसने पुराने पड़ चुके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) का स्थान लिया है। उचित रूप से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय भवन, वाणिज्य भवन, का निर्माण उस भूमि पर किया गया है जहां कभी डीजीएसएंडडी हुआ करता था।



पीयूष गोयल स्वतंत्र लेखक

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाों और सहकारी समितियों ने किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख ऑनलाइन लेनदेन के जरिए दो लाख करोड़ रुपये (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की। यह समावेशी विकास, पारदर्शिता, दक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्धता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

जीईएम सही अर्थों में एक रत्न है। इसने पुराने पड़ चुके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) का स्थान लिया है। उचित रूप से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय भवन, वाणिज्य भवन, का निर्माण उस भूमि पर किया गया है जहां कभी डीजीएसएंडडी हुआ करता था। इस भवन के शिलान्यास समारोह में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सही ही कहा था: अब 100 साल से अधिक पुराने इस संगठन को बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर डिजिटल तकनीक पर

आधारित एक नए निकाय - गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस झू को लाया गया है। जीईएम ने सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है।

अगस्त 2016 में स्थापित होने के बाद से, जीईएम के कामकाज में असाधारण प्रगति हुई है। इस पोर्टल पर होने वाले लेनदेन का कुल मूल्य 2022-23 में लगभग दोगुना होकर पिछले वित्तीय वर्ष में 1.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 422 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ इसकी अनूठी यात्रा शुरू हुई थी। इस पोर्टल का शुभारंभ वस्तुओं एवं सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मिशन और सरकारी प्रणालियों की ईमानदार, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की उनकी रणनीति के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से किया गया था।

जीईएम की प्रतिस्पर्धी बोली जैसी पारदर्शी कार्यप्रणालियों ने सरकारी विभागों एवं उपक्रमाों को करदाताओं के लगभग 40,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद की है। इस तरह की



निर्मल रानी लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

देश की जनता तक प्रधानमंत्री की अपनी बात पहुंचाने का इकरफा संवाद कार्यक्रम मन की बात का सौवां एपिसोड गत 30 अप्रैल (रविवार) को अभूतपूर्व प्रचार के बीच पूरे उत्सव के रूप में प्रसारित किया गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद 3 अक्टूबर 2014 को इस रेडिओ कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। 30 अप्रैल को, प्रसारित किये गये इस शतकीय एपिसोड को देश विदेश में अधिक लेखकों ने अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये युद्धस्तरीय तैयारियां की गयी थीं। देशभर के करीब 4 लाख केंद्रों में सामूहिक रूप से सुने गये इस कार्यक्रम को देश की अनेक संस्थाएं अधिक जनता के बीच आने के लिये देश भर की भाजपाईं सरकारों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, सांसदों, विधायकों आदि सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस प्रसारण के कई दिन पहलू से ही देश भर के सैकड़ों भाजपाईं महत्वियों, नेताओं व सत्ता समर्थक अनेक लेखकों ने कार्यक्रम की तारीफ संबंधी आलेख देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा कर

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस: एक बहुमूल्य रत्न!

इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाों और सहकारी समितियों ने किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख ऑनलाइन लेनदेन के जरिए दो लाख करोड़ रुपये (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की। यह समावेशी विकास, पारदर्शिता, दक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्धता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। जीईएम सही अर्थों में एक रत्न है। इसने पुराने पड़ चुके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) का स्थान लिया है। उचित रूप से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय भवन, वाणिज्य भवन, का निर्माण उस भूमि पर किया गया है जहां कभी डीजीएसएंडडी हुआ करता था।



पहलों ने मोदी सरकार को राजकोषीय स्थिति से समझौता किए बिना उल्लेखनीय कार्यें पर होने वाले व्यय में कल्याणवीय वृद्धि करने में मदद की है। कई अर्थों में, जीईएम लोगों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पक्ष में जबरदस्त मतदान किए जाने के बाद से शासन-प्रशासन में लाए गए बदलावों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। लोग पिछली सरकार से तंग आ चुके थे, जो हमेशा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहती थी। उस सरकार के कई मंत्रियों के लिए तो विभिन्न अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर छपने वाली शर्म और लांछन की रोज की खुराक ही उनकी जीवनशैली का एक आधार थी। इस संदर्भ में, जीईएम का महत्व वित्तीय दृष्टि से इसकी अभूतपूर्व वृद्धि से कहीं अधिक है और यह अपने-आप में ई-गॉर्नास की किसी भी बड़ी कंपनी को ईर्ष्या में भर देने के लिए काफी है। इस नई प्रणाली ने सदियों पुरानी उन प्रक्रियाओं की जगह ली है जो अक्षमताओं और भ्रष्टाचार से प्रस्त थीं। सरकारी खरीद अपारदर्शी, काफी समय लेने वाली, बोझिल और भ्रष्टाचार एवं निर्मातों की गुटबंदी (काटेलांइजेशन) में लिप्त हुआ आर करती थी। केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही प्रवेश संबंधी विशाल बाधाओं



को पार कर पाते थे। खरीदारों के पास विशेषाधिकार प्राप्त और अक्सर रईमान आपूर्तिकर्ताओं से ऊंची एवं बिना मोल-भाव वाली कीमतों पर घटिया सामान खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जबकि संधावित विक्रेताओं को सूचीबद्ध होने और फिर समय पर भुगतान पाने के लिए पूरी तरह से सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की दया पर निर्भर रहना होता था और दर-दर भटकना पड़ता था। इसके उलट, इस प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म के जरिए विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर देने और भुगतान की प्रक्रिया में शायद ही कोई मानवीय हस्तक्षेप शामिल होता है। हर कदम पर खरीदार, उसके संगठन के प्रमुख, भुगतान करने वाले अधिकारियों और विक्रेताओं को एसएमएस और ई-मेल के जरिए सूचनाएं दीं जाती हैं।

कागजरहित, नकदरहित और फेसलेस जीईएम की यह प्रणाली खरीदारों को असंख्य विक्रेताओं से सीधे प्रतिस्पर्धा दरों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करने की आजादी देता है। यह नई प्रतिस्पर्धी प्रणाली प्रधानमंत्री श्री मोदी की डिजिटल इंडिया की पहल पर आधारित क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक और कदम है। इसने सार्वजनिक



खरीद के तौर-तरीकों को बदल दिया है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और छोटे व्यापारियों के लिए लोकप्रिय सरकारी आर्डर हासिल करना संभव बनाया है।

ठोस आंकड़े और तीसरे-पक्ष द्वारा किए गए व्यावहारिक विश्लेषण जीईएम की सफलता की पुष्टि करते हैं। विश्व बैंक और आईआईएम लखनऊ द्वारा किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन में औसत मूल्य से औसतन 10 प्रतिशत की बचत का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक का कहना है कि प्रत्येक नए बोलौदाता के जुड़ने से बचत में 0.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के एक अध्ययन से यह पता चला है कि 2021-22 में वार्षिक लागत बचत 8 प्रतिशत -11 प्रतिशत के दायरे में थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सही ही जीईएम के उद्देश्य को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम आसानी, दक्षता व पारदर्शिता के रूप में अभिप्व्यक्त किया है। इस पोर्टल पर 32 लाख 2021-22 में वार्षिक लागत बचत 8 प्रतिशत -11 प्रतिशत के दायरे में थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सही ही जीईएम के उद्देश्य को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम आसानी, दक्षता व पारदर्शिता के रूप में अभिप्व्यक्त किया है। इस पोर्टल पर 32 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 11,500 से अधिक उत्पाद श्रेणियां उपलब्ध हैं। इनमें 280 से अधिक श्रेणियां सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और ये 2.8 लाख से अधिक सेवा संबंधी पेशकश करती हैं। जीईएम 67,000

प्रचार के उत्कर्ष व संवेदनहीनता के बीच मन की बात का शतक

2014 में सत्ता में आने के बाद 3 अक्टूबर 2014 को इस रेडिओ कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। 30 अप्रैल को, प्रसारित किये गये इस शतकीय एपिसोड को देश विदेश में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये युद्धस्तरीय तैयारियां की गयी थीं। देशभर के करीब 4 लाख केंद्रों में सामूहिक रूप से सुने गये इस कार्यक्रम को देश की अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने के लिये देश भर की भाजपाईं सरकारों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, सांसदों, विधायकों आदि सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस प्रसारण के कई दिन पहले से ही देश भर के सैकड़ों भाजपाईं मंत्रियों, नेताओं व सत्ता समर्थक अनेक लेखकों ने कार्यक्रम की तारीफ संबंधी आलेख देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा कर कार्यक्रम की तारीफ के पुल बाँधने शुरू कर दिये थे।



देश की जनता तक प्रधानमंत्री की अपनी बात पहुंचाने का इकरफा संवाद कार्यक्रम मन की बात का सौवां एपिसोड गत 30 अप्रैल (रविवार) को अभूतपूर्व प्रचार के बीच पूरे उत्सव के रूप में प्रसारित किया गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद 3 अक्टूबर 2014 को इस रेडिओ कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। 30 अप्रैल को, प्रसारित किये गये इस शतकीय एपिसोड को देश विदेश में अधिक लेखकों ने अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये युद्धस्तरीय तैयारियां की गयी थीं। देशभर के करीब 4 लाख केंद्रों में सामूहिक रूप से सुने गये इस कार्यक्रम को देश की अनेक संस्थाएं अधिक जनता के बीच आने के लिये देश भर की भाजपाईं सरकारों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, सांसदों, विधायकों आदि सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस प्रसारण के कई दिन पहलू से ही देश भर के सैकड़ों भाजपाईं महत्वियों, नेताओं व सत्ता समर्थक अनेक लेखकों ने कार्यक्रम की तारीफ संबंधी आलेख देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा कर

मेरे लिए सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूजा और व्रत की तरह है।मन की बात मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने के जैसा ही रहा है।प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात करोड़ों भारतीयों के मन की बात है। यह उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। उन्होंने कार्यक्रम में पूर्व के सेल्फी विद डॉटर अभियान को जिऊ करतो हूए कहा कि ये सेल्फी का मुद्दा नहीं था बल्कि ये बेटियों से जुड़ा था जिसमें लोगों ने बहुत शानदार तरीके से भाग लिया। इस अभियान का मकसद लोगों को जीवन में बेटी के महत्व को समझाना था। जिस समय प्रधानमंत्री बेटियों संबंधी अपने मन के उदगार पेश कर रहे थे ठीक उसी समय जंतर मंतर पर धरने पर बैठी

ये बेटियां भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बढ़ते गौर से सुन रही थीं जो देश के लिये विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत कर लाई हैं और विश्व में देश और राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ाया है।कथित तौर पर एक भाजपाईंसांसद के यौन उत्पीड़न की शिकार देश की गौरव यह बेटियां जानना चाह रही थीं कि जो प्रधानमंत्री मन की बात के

से जुड़ा देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, बढ़ती आर्थिक असमानता, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की ब्रेताशा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व गैस के रिकार्ड मूल्य, किसान संगठनों से किए गए वादों को पूरा करने व भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा इस कार्यक्रम में नहीं की गयी।जोकि वास्तव में सीधे तौर पर देश की जनता से जुड़े विषय हैं। परन्तु अफसोस की बात है कि देश की गंभीर व महत्वपूर्ण विषय भाजपा नेता व पूर्व राज्यपाल सतपाल मालिक का एक और अति गंभीर आरोप कश्मीर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उन्होंने आप एस एस के एक वरिष्ठ नेता का नाम लेकर कुछ तथ्य उजागर किये। इसी प्रकार सतपाल मालिक का एक और अति गंभीर आरोप कश्मीर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उन्होंने आप एस एस के एक वरिष्ठ नेता का नाम लेकर कुछ तथ्य उजागर किये।

देश में घुम घूम कर भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री आखिर सतपाल मालिक के इतने बड़े रहस्योद्घाटन पर भी खामोश क्यों रहे? इसतरह के गंभीर विषयों को मन की बात में शामिल न करना निश्चित रूप से इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये विश्व करता है कि प्रचार के उत्कर्ष व संवेदनहीनता के बीच पर उत्सव की तरह मन की बात का शतकीय एपिसोड प्रसारित किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण ने अप्रैल 2023 माह में छुआ उच्चतम स्तर

प्रहलाद सबनानी

भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत ही अप्रैल 2023 माह से हुई है एवं नए वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में ही अर्थात् अप्रैल 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 187, 035 करोड़ रुपए का रहा है और यह एक नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। पूर्व में अप्रैल 2022 माह में यह 167, 540 करोड़ रुपए का रहा था, जो उस समय पर एक नया रिकार्ड स्तर बना था। अप्रैल 2023 माह में यह अप्रैल 2022 माह की तुलना में 19, 495 करोड़ रुपए अधिक रहा है एवं 11.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 160, 172 करोड़ रुपए का रहा था एवं वर्ष 2022-23 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण का मासिक

औसत 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। इसी प्रकार, अप्रैल 2023 माह में ही यूपीआई व्यवहारों ने भी अभी तक के एक नए रिकार्ड स्तर को छुआ है और 14.07 लाख करोड़ रुपए के 890 करोड़ व्यवहारों के साथ अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही, फास्टेज व्यवहार भी अप्रैल 2023 माह में 5149 करोड़ रुपए के 30, 50, 000 व्यवहारों के साथ अभी तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए है। फास्टेज व्यवहारों में अप्रैल 2023 माह में 15 प्रतिशत एवं राशि के संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।इससे भारत में उत्पादों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने को अत्यधिक तेज गति मिलती दिखाई दे रही है। इन व्यवहारों में वृद्धि देश में आर्थिक विकास की दर को और आगे ले जाने में मदद करेगी।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में लगातार हो रही वृद्धि में कुछ राज्यों का योगदान निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है एवं भारत में यह सहकारी संवेदाद करने में निश्चित ही आसानी होगी।

उक्त दस बड़े राज्यों में से कुछ राज्यों सहित कुछ अन्य राज्यों ने अप्रैल 2022 की तुलना में अप्रैल 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। अर्थात्, इन राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज होती दिखाई दे रही है। ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत), हरियाणा (22 प्रतिशत), जम्मू एवं काश्मीर (44 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (28 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21 में) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं तमिलनाडु ने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को आगे आने वाले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर ले जाने

के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में हो रही वृद्धि के चलते इन राज्यों को उक्त लक्ष्य हासिल करने में निश्चित ही आसानी होगी।

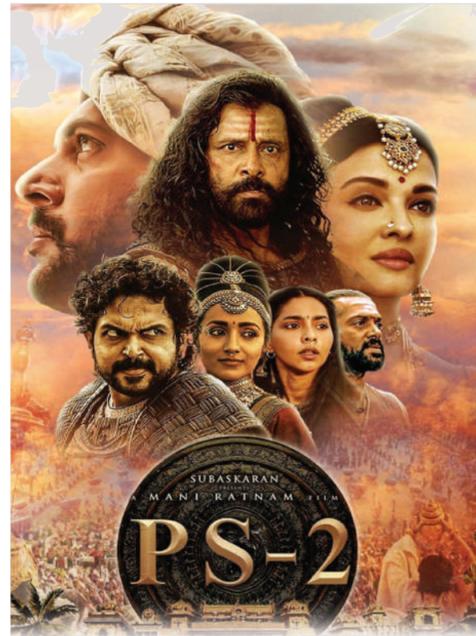
उक्त दस बड़े राज्यों में से कुछ राज्यों सहित कुछ अन्य राज्यों ने अप्रैल 2022 की तुलना में अप्रैल 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। अर्थात्, इन राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज होती दिखाई दे रही है। ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत), हरियाणा (22 प्रतिशत), जम्मू एवं काश्मीर (44 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (28 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21 में) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुवा (32 प्रतिशत) एवं लद्दाख (43 प्रतिशत)।

विशेष रूप से पिछले 9 वर्षों से भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के

विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण के अप्रैल 2023 माह के आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के उक्त प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। अर्थात्, इन राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज होती दिखाई दे रही है। ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत), हरियाणा (22 प्रतिशत), जम्मू एवं काश्मीर (44 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (28 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21 में) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा (32 प्रतिशत) एवं लद्दाख (43 प्रतिशत)।

विशेष रूप से पिछले 9 वर्षों से भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के

समय समय पर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करता दिखाई देता है। इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में अप्रैल 2023 माह के दौरान सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले 8 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार अथवा केंद्र सरकार का सीधा शासन है। साथ ही उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में से लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की अथवा केंद्र की समर्थित सरकार है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यदि एक ही दल अथवा गठबंधन की हो तो (डबल इंजन की सरकार वाले राज्य) क्या वास्तव में देश के आर्थिक विकास को यह मॉडल गति देने में सहायक बनता प्रतीत हो रहा है, इस विषय पर विचार किए जाने की आज आवश्यकता है।



पोन्नियन सेल्वन 2 ने वर्ल्डवाइड की 200 करोड़ की कमाई

ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म पोन्नियन सेल्वन सेल्वन 2 ने रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपए की कमाई पूरी कर ली है। डायरेक्टर मणि रत्नम की एंटरटेनमेंट कंपनी मद्रास टॉकीस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म के 200 करोड़ बलब में एंटी करने की जानकारी दी। फिल्म 28 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी।

मद्रास टॉकीज के वीडियो शेर कर की जानकारी
मद्रास टॉकीज के टिवटर हैंडल ने फिल्म की कमाई बताते हुए छोटी वीडियो विलप शेर कर कर लिखा- पीएस 2 ने लंबी छलांग मारी है। फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपए की कमाई पूरी कर ली है। साथ ही हेस्टिंग के साथ लिखा- चोला वापस आ गए हैं। पीएस 2 बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इस पोस्ट पर एक फैन ने लिखा- सिर्फ 4 दिनों में 200 करोड़ बलब में शामिल हो गई पीएस-2! इसका मतलब है कि ये फिल्म 45+ दिनों में करीब 3000+ भी कर सकती है। वहीं, एक यूजर ने साउथ इंडियन एक्ट्रेस तुषा और तमिल एक्टर कार्थी को टैग करते हुए लिखा- ये कमाई आपकी है।

कृष्णमूर्ति की नॉवेल पोन्नियन सेल्वन पर बेस्ड है फिल्म
पोन्नियन सेल्वन 2, 2022 में रिलीज हुई फिल्म पोन्नियन सेल्वन का सीकल है। फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति की नॉवेल पोन्नियन सेल्वन पर बेस्ड है। फिल्म पोन्नियन सेल्वन कल्कि कृष्णमूर्ति की नॉवेल के तीन पार्ट्स पर बेस्ड थी। जबकि, पोन्नियन सेल्वन 2 बचे हुए दो पार्ट्स पर बेस्ड है। फिल्म में ऐश्वर्या राय, विक्रम, तुषा, जयराम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धुलिपाल, प्रकाश राज, जयाम, प्रभु, आर सारतकुमार, पार्थीब, विक्रम प्रभु जैसे एक्टर्स ने चोला साम्राज्य की कहानी को आगे बढ़ाया है। एक्टर कमल हसन ने फिल्म का नैरेशन किया है। ए आर रहमान ने फिल्म को म्यूजिक दिया है। मणि रत्नम के मद्रास टॉकीज और सुबासकरण के लाइका प्रोडक्शन में फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किया है।

ऐश्वर्या ने फिल्म में किया है डबल रोल
फिल्म में जयाम (रवि मोहन) ने राजराजा चोला 1 का किरदार निभाया है जबकि ऐश्वर्या ने डबल रोल किया है। ऐश्वर्या ने पद्मवती की खूबसूरत रानी नदिनी और उनकी मां मंदाकिनी देवी दोनों का रोल किया है। वहीं तुषा ने चोला साम्राज्य की राजकुमारी कुंदवाई का किरदार निभाया है। ये फिल्म वर्ल्डवाइड हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज हुई है। फिल्म का नाम चोला साम्राज्य के पहले राजराजा 1 - अरुलमोड़ी वर्मन के दूसरे नाम से लिया गया है। इसका मतलब है- कावेरी पुत्र। दरअसल, ऐसा माना जाता है कि बचपन में राजराजा को कावेरी नदी ने डूबने नहीं दिया था और उनकी जान बचाई थी। इसलिए उन्हें कावेरी पुत्र भी कहा जाता है।



डेब्यू करते ही शहनाज गिल के हाथ लगी लॉटरी, जमकर मिल रही बधाई

रियलिटी शो का हिस्सा बनकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शहनाज गिल ने फाइनेली सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है। यू तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन पंजाब की कटरीना कैफ की एक्टिंग को दर्शक काफी सराह रहे हैं। वहीं, डेब्यू के साथ ही शहनाज ने नया घर खरीद लिया है, जिसकी खुशी एक्ट्रेस बकायदा पोस्ट कर साझा करती नजर आई हैं। शहनाज गिल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर कुछ स्क्रीनशॉट्स साझा किए हैं, जिनमें उनके लिए फैंस की ओर से आई बधाई है। ये बधाई शहनाज के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर नहीं बल्कि उनके नए घर को लेकर है। हालांकि, शहनाज ने अपना नया घर मुंबई के किस इलाके में खरीदा है और इसकी कीमत क्या है इसको लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। शहनाज गिल ने बीते दिन अपने चेट शो देसी वाइब्स में बतौर गेस्ट आए यूट्यूबर भुवन बाम को बताया था कि उन्होंने मुंबई में नया घर खरीदा है, लेकिन उसमें आने के लिए गेस्ट को कुछ नियम फॉलो करने होंगे। इस तरह, सना की सफलता को देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं और दिल खोलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो, शहनाज गिल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रियलिटी शो बिग बॉस 13 से एंटी ली थी। इसके बाद उन्हें अपने चेट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल से खूब सफलता हासिल हुई है। वहीं, एक्ट्रेस ने भाईजान सलमान खान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए बड़े पर्दे पर पांच जमाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा शहनाज म्यूजिक एल्बम में भी खासा एक्टिव देखी जाती हैं।

कियारा ने पूरी की सत्यप्रेम की कथा की शूटिंग

भूल भुलैया 2 की जबरदस्त सफलता के बाद कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी एक बार फिर फिल्म सत्यप्रेम की कथा में नजर आने वाली है। वहीं अब कियारा आडवाणी ने इस फिल्म की अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेर कर रहे हैं इसकी जानकारी दी है। तस्वीर में कियारा आडवाणी केक काटते नजर आ रही हैं। साथ ही कार्तिक आर्यन और फिल्म के वरु मेबरस भी दिख रहे हैं। इसके साथ कार्तिक आर्यन ने लिखा, कुछ दिन बाकी हैं लेकिन अब बिना कथा की शूटिंग खाली-खाली लगेगी... सत्यप्रेम को कथा की कमी खलेगी। इसके साथ कार्तिक ने कियारा की पोस्ट को भी रिपोस्ट किया है। इसमें लिखा है, यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, एक ऐसी यात्रा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, एक ऐसा अनुभव जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। सबसे भावुक कलाकारों और वरु मेबरस के साथ काम करने का सौभाग्य, जिन्होंने हमारी फिल्म में अपना दिल और आत्मा लगाई है। उन्होंने लिखा, मैंने इस यात्रा में नए दोस्त बनाए हैं जिन्हें मैं हमेशा के लिए प्यार और महत्व दूंगी। मेरे निर्देशक सर, आपने जादू पैदा कर दिया है, कार्तिक आर्यन, शरीन मंत्री, करण शर्मा मुझे ट्रिनिटी याद आएंगी। गजराव सर, सुप्रिया पाठक मेम, अनुराधा पटेल और हमारी पूरी कास्ट बनाने के लिए धन्यवाद मैं आपके शानदार प्रदर्शन के साथ एक बेहतर कलाकार बनी हूँ। और मेरे अपने दस्ते के लिए इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के माध्यम से मेरा ठोस समर्थन करने के लिए धन्यवाद। सत्यप्रेम की कथा, साजिद नाडियाडवाला की एनजीई और शरीन मंत्री के डिवा और किशोर अरोड़ा की नमः पिछर्स के सहयोग से बनाई जा रही है। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान हाल ही में ईद के मौके पर रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूने में फिल्म का दम निकल गया। फेस्टिव रिलीज होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। इस कारण अब सलमान नई

कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे सलमान खान! टाइगर 3 की रिलीज के बाद लेंगे फैसला

फिल्मों को साइन करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। दरअसल, सलमान खान अक्सर ईद के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। इस बार भी ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म उम्मीद के मुकाबले कमाई नहीं कर पाई। खबर आ रही है कि सलमान ने नई फिल्म को साइन करने से मना कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान को छह प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन वह अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन करने से परहेज कर रहे हैं। सलमान खान अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 का इंतजार कर रहे हैं, जो नवंबर में रिलीज होगी। दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की प्रतिक्रिया देखने के बाद ही सलमान अपनी अगली फिल्म को लेकर फैसला करेंगे। फिलहाल, दर्शकों को वह मनीष शर्मा के निर्देशन वाली टाइगर 3 में नजर आएंगे, जिसमें कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में अभिनेता के साथ नजर आएंगी। वहीं, शाहरुख खान का फिल्म में कैमियो रोल होगा। बता दें कि अपनी फिल्मों के साथ-साथ सलमान जान से मारने की मिल रही कई धमकियों को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान सलमान ने अपनी सिक्वोरिटी को लेकर कहा कि सुरक्षा, असुरक्षा से बेहतर है। अब सड़क पर साइकिल चलाकर अकेले कहीं जाना भी मुश्किल नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब मुझे यह समस्या होती है कि जब मैं टैफिक में होता हूँ तो इतनी सिक्वोरिटी होती है कि गाड़ियों के कारण दूसरे लोगों को असुविधा होती है। यह एक गंभीर खतरा है, इसलिए सुरक्षा है।

मुझे खुशी है कि मेरी ये फिल्म बाहुबली जैसी नहीं है
जाने-माने तमिल निर्माता-निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन-भाग एक दुनियाभर में पसंद किया गया। हाल ही में रिलीज हुई दूसरे भाग को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मणिरत्नम ने हमसे अपनी फिल्म, फिल्मों के अनुभव और आने वाले दिनों के प्लान के बारे में खास बातचीत की
आपकी फिल्म पीएस 1 ने पूरी दुनिया में 500 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब पीएस 2 से आपकी क्या उम्मीदें हैं?
हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फिल्म को देखें और उसे पसंद करें। हम इसकी कमाई के आंकड़ों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिल्म बनाने वक्त भी मेरी यही कोशिश थी कि जब पहले भाग को लोगों ने इतना पसंद किया, तो दूसरे भाग को दर्शकों के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी।
क्या आप आगे भी इस तरह की ऐतिहासिक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं?
अगर इमानदारी से कहूँ तो अभी मेरे जहन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है। अभी मैं इस बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ। फिलहाल मेरा कोई दूसरी ऐतिहासिक फिल्म बनाने का विचार नहीं है।

आजकल साउथ की भाषाओं की हिंदी डब फिल्में हिंदी भाषी दर्शकों के बीच काफी पॉप्युलर हो रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है?
मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि अगर हम किसी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं और वह देश के हर कोने में पसंद की जाती है, तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। अगर लोग किसी फिल्म को उसके अच्छे कॉन्टेंट के चलते देखना पसंद कर रहे हैं, तो यह उसके निर्माता और कलाकारों के लिए खुशी की बात है।
दूसरी ओर साउथ की फिल्मों की रीमेक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा और मुश्किल दौर आता रहता है। हो सकता है यह भी वही दौर हो। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। उनमें बहुत सारे अच्छे फिल्ममेकर्स और एक्टर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम इस फेज से भी निकल जाएंगे और अच्छी फिल्में आएंगी।

साउथ की हिंदी में डब सफलतम फिल्मों की बात करें, उनमें तेलुगु की बाहुबली, आरआरआर, पुष्पा तथा कन्नड़ की केजीएफ और कांतारा का नाम प्रमुख हैं। लेकिन तमिल फिल्मों ने ऐसा कोई कमाल नहीं किया?
मैंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है। आपने ही मुझे इस बारे में बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फिल्म पीएस 2 इस संदेश को दूर करेगी।
बहुत से लोग पीएस 1 की फिल्म बाहुबली से तुलना करते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा मानना है कि यह फिल्म बाहुबली जैसी नहीं लगती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। यह एक ऐतिहासिक फिक्शन है, लेकिन यह अभी भी वास्तविकता से थोड़ी अलग है। इसलिए मुझे खुशी है कि यह बाहुबली जैसी नहीं है। हर फिल्ममेकर अपनी अगली फिल्म को पिछली फिल्मों से अलग बनाना चाहता है।

पिछले दिनों आपने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खुद को बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए। क्या इससे भाषाई फिल्म इंडस्ट्री के मदद मिलेगी?
नहीं इससे दूसरी भाषाओं की इंडस्ट्री के लिए मदद नहीं होगी, बल्कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अच्छा रहेगा। इससे दुनिया में लोग भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से नहीं जानेंगे।
ओटीटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आप ओटीटी के लिए भी कुछ बनाना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि यह हर फिल्ममेकर के लिए अच्छा मौका है। जब फिल्ममेकर के पास कोई बड़े फॉर्मेट वाली कहानी हो, तो आप हर कहानी को दो या ढाई घंटे के समय में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कई अच्छे फिल्ममेकर पहले से ही बड़े फॉर्मेट वाली कहानियों पर काम कर रहे हैं। ये अच्छी चीज है।





संसेक्स

61112.44 पर बंद

निफ्टी

18065.00 पर बंद

ब्यापार

सोना

59,092

चांदी

70128

एसी या फिज खरीद रहे हैं तो समझ लें, एक स्टार बढ़ने से जेब ढीली होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। गर्मियों जैसे-जैसे बढ़ रही है बाजार में एसी, फिज से लेकर कुलर तक लोग खूब खरीद रहे हैं। बाजार में आजकल मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर स्टार रेटिंग दी जाती है। शी स्टार वाले प्रोडक्ट सबसे होते हैं। वहीं 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स के दाम ज्यादा होते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर यह रेटिंग उनकी बिजली की खपत के आधार पर दी जाती है। 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट बिजली की कम खपत करते हैं। इसका असर सीधा आपके बिजली के बिल पर पड़ता है। लेकिन फाइव स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट के लिए कितने रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं और इनमें कितनी बचत होती है? क्या 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स लेना मुनाफे का सौदा रहता है। आइए समझते हैं स्टार रेटिंग और इससे होने वाली बचत का पूरा गणित।



3 स्टार खरीदें या 5 स्टार

5 स्टार फिज पर कितनी बचत होगी: अगर शी स्टार और 5 स्टार फिज की बात करें तो आमतौर पर दोनों के बीच करीब 3600 रुपये से 4 हजार रुपये का अंतर रहता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और शी स्टार फिज एक साल में करीब 14977के2एच बिजली की खपत करते हैं। इस हिसाब से एक साल में यह 7489 रुपये की बिजली खर्च

देखें तो शी की जगह 5 स्टार फिज खरीदने पर एक साल में आपके करीब 2803 रुपये बचेंगे। वहीं मुंबई में रहने वालों के 4485 रुपये बचेंगे।

5 स्टार एसी कितने रुपये बचाएंगे: बाजार में मिलने वाले शी और फाइव स्टार रेटिंग वाले एसी की बात करें तो दोनों के दाम में करीब 9500 से 10 हजार रुपये का अंतर है। अगर आप 1.5 टन एसी को रोजाना 8 घंटे चलाते हैं तो शी स्टार हर दिन 13.36के2एच बिजली की खपत करेगा। वहीं 5 स्टार हर दिन 10.56के2एच बिजली की खपत करेगा। इस हिसाब से दिल्ली में रहने वाले अगर छह महीना 5 स्टार एसी खरीदते हैं तो करीब 2560 रुपये बचाएंगे। मुंबई में रहने वाले 5 महीने में ही 3427 रुपयों की बचत कर लेंगे। इस तरह से करीब 3 साल 9 महीने में 5 स्टार एसी के लिए थिए गए अतिरिक्त रूपये वसूल हो जाएंगे। वहीं अगर हर साल बिजली के बिल में करीब 25 फीसदी की बचत करेंगे।

अडानी विलमर का चौथी तिमाही का मुनाफा 60 प्रतिशत घटकर 93.61 करोड़ रुपए पर

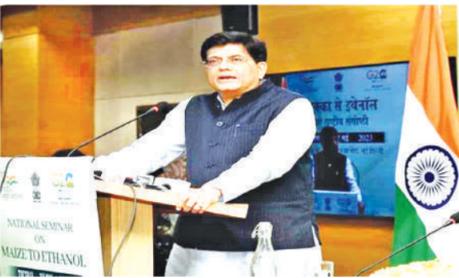
नई दिल्ली, एजेंसी। खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अडानी विलमर का बीते वित्त वर्ष की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 60 प्रतिशत घटकर 93.61 करोड़ रुपए रह गया है। आमदनी घटने से कंपनी का मुनाफा भी नीचे आया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 234.29 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय घटकर 13,945.02 करोड़ रुपए पर रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 14,979.83 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में अडानी विलमर का शुद्ध लाभ 803.73 करोड़ रुपए से घटकर 582.12 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की आय बढ़कर 58,446.16 करोड़ रुपए हो गई। 2021-22 में यह आंकड़ा 54,327.16 करोड़ रुपए था। अडानी विलमर फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है। इसके अलावा कंपनी चालत और चीनी जैसे अन्य खाद्य उत्पाद भी बेचती है।

पंजाब में अनाज आधारित एथनॉल संयंत्र लगाएगी जगतजीत इंडस्ट्रीज

नई दिल्ली, एजेंसी। शराब कंपनी जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजाब में अनाज आधारित एथनॉल विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए 210 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी की एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम का मकसद हरित ईंधन की पेट्रोल में मिश्रण के लिए बढ़ती मांग का लाभ उठाना है। वर्ष 1944 में स्थापित जगतजीत इंडस्ट्रीज देश में भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) और देशी शराब के विनिर्माण की अग्रणी कंपनियों में से है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनी के विनिर्माण संयंत्र कापूरथला (पंजाब) और बहरोडा (राजस्थान) में हैं। जगतजीत इंडस्ट्रीज की प्रवर्तक और मुख्य पुनर्गठन अधिकारी रोशनी स्नाहा जायसवाल ने कहा, "हम पंजाब के कापूरथला जिले के हमीरा में 200 किलो लीटर प्रतिदिन (200 केएलपीडी) क्षमता के साथ एक नया अनाज आधारित एथनॉल संयंत्र लगा रहे हैं।

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक हासिल कर लेंगे: गोयल



नई दिल्ली, एजेंसी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भरोसा जताया कि 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को लागू करने में मक्के की फसल की प्रमुख भूमिका होगी। गोयल ने 'मक्के से एथनॉल विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि एथनॉल एक 'उभरता हुआ क्षेत्र है। उन्होंने उद्योग से इस हरित ईंधन को बनाने के लिए एंसे कारखाने लगाने को कहा, जो दो कच्चे माल (गन्ना और खाद्यान्न) पर काम कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों और उद्योग के प्रयास से पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण को बढ़कर 2021-22 में 10 प्रतिशत कर दिया गया जो 2013-14 में 1.53 प्रतिशत था। गोयल ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल

रॉकेट बन गया सरकारी कंपनी का यह शेयर, हर दिन कर रहा मालामाल

नई दिल्ली, एजेंसी। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर लगातार तेजी से चढ़ रहे हैं। आज बुधवार के कारोबार में आरवीएनएल का शेयर 52-वीक के हाई 130 पर पहुंच गया। स्टॉक मंगलवार को बीएसई पर बंद भाव 118.40 से 3.8 प्रतिशत बढ़कर 123 प्रति शेयर पर खुला था। दिनभर के कारोबार में स्टॉक लगभग 10 प्रतिशत बढ़ गया था। आरवीएनएल के शेयरों में तीन कारोबारी सत्रों में 26 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक महीने में यह शेयर 72.66 प्रतिशत चढ़ गया है। इस साल वायटीडी में 89.79 प्रतिशत चढ़ है। सालभर में आरवीएनएल के शेयर 294.24 प्रतिशत चढ़ गए हैं।

शेयरों में तेजी की वजह: आरवीएनएल के शेयरों में तेजी के कई कारण हैं। बता दें कि रेलवे फर्म को कई ऑर्डर मिलने और नवर प्रतिशत का दर्जा मिलने के बाद शेयरों में उछाल आया है। कंपनी को एक के बाद एक कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। आरवीएनएल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा (राजस्थान) ऑन इंजीनियरिंग, प्रोक्सिमेट एंड कंस्ट्रक्शन (ईसीसी) सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्नकी आधार, जिसमें 10 साल का ओएंडएम शामिल है। परियोजना की लागत 2,249 करोड़ रुपये है (आरवीएनएल का हिस्सा 5.1 प्रतिशत है और एससीसी का हिस्सा 49 प्रतिशत है)। कंपनी ने चेन्नई मेट्रो रेल (सीएमआरएल) चरण-द्वितीय परियोजना के तीन भूमिगत पैकेजों के लिए कुल 3,146 करोड़ रुपये का अनुबंध भी जीता। इसके अलावा, बीएसई के साथ हाल ही में कॉर्पोरेट फाइलिंग में, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आरवीएनएल को नवर प्रतिशत का दर्जा दिया। इस कंपनी पर पड़ रही चर्चा, निवेशक फटाफट बेचने लग गए शेयर, 14 प्रतिशत टूट गया भाव

तया है टारगेट प्राइस

ट्रेडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, स्टॉक का औसत टारगेट प्राइस 86 रुपये है। रेल विकास निगम के लिए दो एनालिस्ट की आम सहमति की सिफारिश एक मजबूत बाय की है। तकनीकी रूप से आरवीएनएल 8 में से 8 एप्सए से ऊपर कारोबार कर रहा है।

18 साल बाद आ रहा टाटा की कंपनी का आईपीओ, सेबी की मिली मंजूरी, दांव लगाने के लिए रहे तैयार



नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप शेयर बाजार में दांव लगा कर कमाई करने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका आ रहा है। दरअसल, सालों बाद एक बार फिर टाटा ग्रुप की एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टाटा प्ले के आईपीओ की। टाटा प्ले के आईपीओ को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने हरी झंडी दे दी है। टाटा समूह की फर्म भारत की पहली कंपनी है जिसने आईपीओ के लिए बाजार नियामक के पास गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं। सेबी ने 26 अप्रैल को कंपनी के प्री-फिस्ड ऑफर डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन लेटर जारी किया था। टाटा प्ले 18 साल में आईपीओ लाने वाली समूह की पहली कंपनी हो सकती है। बाजार के सूत्रों के मुताबिक, कंपनी, कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसमें फ्रेश और सैकेंडरी शेयर सेल का मिश्रण हो सकता है। बता दें कि टाटा प्ले को अब आईपीओ लॉन्च करने से पहले एक अपडेटेड ड्रॉपर रीड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस (यूडीआरएफपी-1) दाखिल करना होगा। टाटा मोटर्स की सहजक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी मार्च में अपना ड्रॉपर रीड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस दायर किया था। उम्मीद है कि कंपनी को जल्द ही बाजार नियामक से हरी झंडी मिल जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ करीब 4,000 करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है।

देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अप्रैल में लगभग 13 साल के उच्चस्तर पर



नई दिल्ली, एजेंसी। देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अप्रैल में करीब 13 साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई। एक मासिक सर्वे में बुधवार को यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मजबूत मांग परिस्थितियों से नए कारोबार और उत्पादन में काफी तेज वृद्धि देखने को मिली। खास बात यह है कि कीमत के मोचे पर दबाव के बावजूद मांग बढ़ी है। मौसमी रूप से समायोजित एंज्रूपी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई सूचकांक अप्रैल में बढ़कर 62 पर पहुंच गया। यह मार्च में 57.8 के स्तर पर था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में 2010 के मध्य के बाद सबसे तेज विस्तार हुआ है। अनुकूल बाजार परिस्थितियों तथा नए कारोबार में वृद्धि से सेवा पीएमआई यह उछाल दर्ज हुआ है। यह लगातार 21वां महीना है जबकि सेवा पीएमआई 50 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के 50 से ऊपर होने का मतलब विस्तार से होता है। यदि यह 50 से नीचे है, तो गिरावट को दर्शाता है। एस्पेंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेल्जेंस में एसोसिएट निदेशक (इकॉनॉमिक्स) पॉलियाना डि लीमा ने कहा, "भारत के सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अप्रैल में काफी शानदार रहा है। इस दौरान नए कारोबार और उत्पादन में वृद्धि पिछले करीब 13 साल में सबसे अधिक रही है। सबसे बेहतर प्रदर्शन वित्तीय और बीमा क्षेत्र ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने संकेत दिया है कि अप्रैल में जबकि सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में खासा सुधार हुआ है। नया निर्यात कारोबार लगातार तीसरे महीने बढ़ा है। हालांकि, मूल्य के मोचे पर बात की जाए, तो अप्रैल में उत्पादन लागत पिछले तीन माह में सबसे तेजी से बढ़ी है। सर्वे के अनुसार, खाने-पीने का सामान, ईंधन, दवाएं, परिवहन और मजदूरी मुद्रास्फीति की प्रमुख वजह हैं। उपभोक्ता सेवाओं पर औसत खर्च में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिली है।

वैश्विक नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत: रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में आगामी वर्षों में वैश्विक नैदानिक परीक्षणों (क्लिनिकल ट्रायल) में पांच गुना तक बढ़ोतरी करने की क्षमता है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बायोफार्मा कंपनियों के पास भारत की समृद्ध विविधता और मजबूत स्वास्थ्य सेवा ढांचे के जरिये नवोन्मेषी इलाज विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। यूरोप, इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स और पीडब्ल्यूसी इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भारत नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। "भारत में नैदानिक परीक्षण के अवसर" शीर्षक वाली रिपोर्ट बोस्टन में बुधवार को आयोजित होने वाले 17वें वार्षिक जैव फार्मा एंड स्वास्थ्य सेवा शिखर बैठक-2023 के वर्चुअल संस्करण में जारी की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चिकित्सकों और मरीजों के पास तेज पहुंच की वजह से शीर्ष बायोफार्मा कंपनियों के लिए नैदानिक परीक्षण का एक दक्ष माध्यम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वैश्विक नैदानिक परीक्षणों को पांच गुना तक बढ़ाने की क्षमता है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय राज्यों में उच्च रोग प्रसार के साथ आधुनिक चिकित्सा ढांचा है। साथ ही यहां मरीजों की जांच के लिए भी बड़ी संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा पहली श्रेणी के शहर हैं। ऐसे में बायोफार्मा कंपनियां नैदानिक परीक्षणों के लिए इन राज्यों को लक्ष्य कर सकती हैं।

कर नीति तय होते ही ऑनलाइन गेमिंग को मिलेगा निवेश: सीतारमण

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी विषयद ऑनलाइन गेम पर कारोपण की नीति लाने पर विचार कर रही है और इसे अंतिम रूप दिए जाने पर इस उद्योग को निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया के दौरे पर आई सीतारमण ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों के एक कार्यक्रम में शिरकात करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के संदर्भ में जीएसटी परिषद के स्तर पर विचार चल रहा है।



उन्होंने कहा कि जीएसटी करारधन के अलावा नियमान से संबंधित मुद्दों पर भी मंत्री-स्तरीय चर्चा जारी है। कोरियाई गेमिंग कंपनी क्राफ्टॉन की तरफ से गेमिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों के बारे में पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, "इस नीति को लेकर निश्चिन्ता आने के साथ ही करारधन अधिक स्पष्ट हो जाएगा और इससे निवेशक आकर्षित होंगे। जीएसटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय करने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री

करती हैं जबकि राज्यों के वित्त मंत्री भी उसका हिस्सा होते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीएसटी परिषद की जून में होने वाली अगली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर ऑनलाइन गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है। कंपोएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में 13,600 करोड़ रुपये पर रहने वाला ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 29,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

स्पाइसजेट की ठप खड़े 25 विमानों को फिर परिचालन में लाने की तैयारी



नई दिल्ली, एजेंसी। स्पाइसजेट अपने 25 ठप खड़े विमानों को पुनः परिचालन में लाने पर काम कर रही है। इन विमानों को दुर्घटना कर परिचालन में लाने के लिए किफायती सेवा देने वाली एयरलाइन ने अबतक 400 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। गो फर्स्ट द्वारा नकदी संकट की वजह से तीन दिन तक उड़ानें निलंबित करने के फैसले के बाद स्पाइसजेट का यह बयान आया है। गो फर्स्ट ने इसके अलावा दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए भी आवेदन किया है। स्पाइसजेट ने बुधवार को बयान में कहा कि 25 विमानों के पुनरुद्धार के लिए पैसा सरकार की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और अन्य माध्यमों से जुटाया जाएगा। एयरलाइन के बेड़े में लगभग 80 विमान हैं। एयरलाइन 25 ठप खड़े बोइंग 737 और 400 विमानों को फिर परिचालन में लाना चाहती है। स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, "हम अपने ठप खड़े विमानों को जल्द सेवा में लाएंगे।" उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस से मिले ज्यादातर वित्तपोषण का इस्तेमाल इस कार्य के लिए किया जाएगा। एयरलाइन पहले ही अपने 40 विमानों को परिचालन में लाने के लिए 400 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। इससे एयरलाइन का राजस्व बढ़ सकेगा। स्पाइसजेट ईसीएलजीएस के तहत पहले ही 500 करोड़ रुपये ले चुकी है। इससे पहले मंगलवार को गो फर्स्ट के मुख्य कार्यवाहक अधिकारी (सीईओ) कौशिक खोना ने कहा था कि प्रेट एंड व्हिटीनी (पीएंडव्हीटी) द्वारा इंजन की आपूर्ति नहीं करने के कारण एयरलाइन ने अपने 28 विमानों को खड़ा कर दिया है। यह उसके बेड़े में शामिल विमानों का आधे से अधिक है।

गो फर्स्ट मामले में मध्यस्थता आदेश का अनुपालन कर रहे हैं: प्रैट एंड व्हिटीनी

नई दिल्ली, एजेंसी। गो फर्स्ट द्वारा दिवाला समाधान के लिए आवेदन दापर करने के एक दिन बाद अमेरिका की इंजन विनिर्माता कंपनी प्रैट एंड व्हिटीनी (पीएंडव्हीटी) ने बुधवार को कहा कि वह एयरलाइन के संबंध में मध्यस्थता आदेश का अनुपालन कर रही है। साथ ही पीएंडव्हीटी ने कहा कि वह सभी ग्राहकों के लिए आपूर्ति की समयसीमा को प्राथमिकता दे रही है। गो फर्स्ट ने पीएंडव्हीटी द्वारा इंजन की आपूर्ति नहीं करने की वजह से ही तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की है। प्रैट एंड व्हिटीनी के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि गो फर्स्ट का इंजन विनिर्माता के प्रति अपनी वित्तीय दायित्वों से चुकने का लंबा इतिहास रहा है। कंपनी ने बयान में कहा, "प्रैट एंड व्हिटीनी अपने एयरलाइन ग्राहकों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सभी ग्राहकों के लिए आपूर्ति समयसीमा को प्राथमिकता दी है। पीएंडव्हीटी गो फर्स्ट से संबंधित मार्च, 2023 के मध्यस्थता फैसले का अनुपालन कर रही है। चूंकि यह मामला अब मुकदमेबाजी में चला गया है, ऐसे में हम इस पर अधिक कुछ नहीं कहेंगे।" इस बीच, गो फर्स्ट ने एक बयान में कहा है कि मध्यस्थ ने पीएंडव्हीटी को 27 अप्रैल तक कम से कम 10 सेवा योग्य अतिरिक्त इंजन पट्टे पर देने का निर्देश दिया है।

10000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा मार्केट कैप, 500 प्रतिशत चढ़े इस सरकारी कंपनी के शेयर, बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने नया मुकाम हासिल किया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 10000 करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली एलीट कंपनी के रूप में शामिल हो गई है। सरकारी कंपनी के शेयरों में बुधवार को अपना 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का मार्केट कैप बुधवार को 100546.98 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिन के कारोबार के दौरान 3032.10 रुपये के हाई पर पहुंच गए।

मोहम्मद शमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हसीन जहां

हसीन ने लगाए संगीन आरोप....होटल में कॉल गर्ल के साथ...

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वाइफ हसीन जहां से विवाह में मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हसीन जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, उन्होंने शमी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेटर वेश्याओं के साथ संबंध बनाता है। खासकर जब वह विदेश दौरों पर होता है। हालांकि, शमी ने इन आरोपों का खंडन किया था।



हसीन ने लगाए संगीन आरोप....होटल में कॉल गर्ल के साथ...

हसीन जहां ने पहली बार 2018 में मोहम्मद शमी के खिलाफ घरेलू दुर्व्यवहार और व्यभिचार के आरोप लगाए थे, जब उन्होंने जादवपुर में पुलिस शिकायत दर्ज की थी। क्रिकेटर की अलगाव हो चुकी पत्नी लगातार शमी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रही हैं। शमी और उनके बड़े भाई हसीब अहमद से 2018 में कोलकाता पुलिस की महिला शिकायत प्रकोष्ठ ने पूछताछ की थी।

ने हसीन जहां द्वारा शमी पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद भी शमी को क्लोन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हसीन जहां की नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोलकाता की सत्र अदालत ने शमी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया, जबकि क्रिकेटर ने अपराधिक मुकदमे के स्थगन के लिए भुगतान भी नहीं किया था और उनकी एकमात्र शिकायत केवल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के खिलाफ थी।

अपनी याचिका में हसीन जहां ने फिर आरोप लगाया है कि शमी दहेज मांगते थे। आईपीएल में चीयरलीडर के तौर पर काम कर चुकी हसीन जहां ने एक चौकाने वाले आरोप में दावा किया है कि मोहम्मद शमी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ दौरों पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनाते रहे हैं। उन्होंने अपने आरोप में कहा- शमी उससे दहेज की मांग करते थे और वे वेश्याओं के साथ अवैध यौन संबंधों में लगातार शामिल रहे हैं। विशेष रूप से अपने बीसीसीआई दौरों

के दौरान, बीसीसीआई की आर से मिले होटल के कमरों में आज भी ऐसा करते हैं।

हसीन जहां ने याचिका में आरोप लगाया है कि शमी अपने दूसरे मोबाइल फोन-एचटीसी कंपनी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते थे। हालांकि, शमी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2023 में कोलकाता की एक अदालत ने शमी को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश के बाद, शमी की ओर से भुगतान की जाने वाली गुजारा भत्ता राशि से हसीन खुश नहीं थी। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज से प्रति माह 10 लाख रुपये की मांग की थी। 2018 में जहां ने 10 लाख रुपये के मासिक गुजारा भत्ता के लिए कानूनी मामला दायर किया, जिसमें व्यक्तिगत खर्चों के लिए 7 लाख रुपये और अपनी बेटी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपये शामिल थे।

राहुल और जयदेव उनादकट आईपीएल 2023 से बाहर, प्रैक्टिस के दौरान आई चोट



नई दिल्ली (एजेंसी)। लखनऊ सुपर जाइंट्स के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट बाएं कंधे की चोट के कारण आईपीएल 2023 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं, जो रविवार को नेट्स प्रैक्टिस के दौरान उठे लग गई थी। हालांकि, अच्छे खबर यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 7 जून से शुरू होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए समय पर फिट हो जाएंगे। राहुल भी आईपीएल से बाहर होने के चांस दिख रहे हैं।

उनादकट रविवार को लखनऊ नेट्स में अपनी पहली गेंद फेंकने जा रहे थे, तभी वह विकेट के चारों ओर से भागे और उनका बायां पैर नेट को ऊपर रखने वाली रस्सी में फंस गया। वह अपनी बॉलिंग एल्बो पर बुरी तरह से गिर गए थे। आईपीएल ने इसका वीडियो भी ट्वीट किया था, लेकिन अब क्रिकइंफो की रिपोर्ट से पता चला है कि वे इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे। उनादकट जल्द ही बैंगलूर की नेशनल क्रिकेट अकादमी में भेजा जा सकता है। वे लखनऊ टीम के मेडिकल स्टाफ के साथ स्कैन के लिए मुंबई गए हैं।

उनादकट डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत की टीम में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और आंलराउंडर शार्दूल ठाकुर के साथ पांच तेज गेंदबाजी विकल्पों में से एक है। केएल राहुल भी डब्ल्यूटीसी टीम में हैं लेकिन अभी तक उनकी भागीदारी स्पष्ट नहीं है। आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में का?तान केएल राहुल हैमरिस्टंग की दिव?कत में आ गए थे, ऐसे में वे खेल नहीं पाए। अपनी टीम के लिए ओपनिंग के लिए आने वाले केएल राहुल आरसीबी के खिलाफ नंबर 11 पर बल?लेबाजी के लिए मुश्किल वक?त में आए और तीन गेंद पर खाता भी नहीं खोल पाए।

बात दें कि जयदेव उनादकट को इस सीजन के 3 मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन वह एक भी विकेट नहीं ले पाए। हालांकि इससे पहले वे अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने आईपीएल में कुल 94 मैच खेले हैं और इस दौरान 91 विकेट लिए हैं। उनका इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है। उनादकट ने आईपीएल 2017 में 24 विकेट झटके थे।

पाटीदार की एड़ी की सर्जरी सफल रही

बंगलुरु (एजेंसी)। रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) के क्रिकेटर रजत पाटीदार की चोटिल एड़ी की सर्जरी सफल रही। पाटीदार इस चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र से बाहर है। मध्य प्रदेश के 29 वर्षीय क्रिकेटर को आईपीएल सत्र से पहले आरसीबी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले चोट लग गई थी। बाद में उन्हें रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) के लिए बंगलुरु में राष्ट्रीय क्रीडा केंद्र अकादमी (एनसीए) भेजा गया था। पिछले साल आईपीएल में अपना पहला शतक जड़ने वाले पाटीदार ने प्ले-ऑफ में नाबाद 112 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले सत्र में आठ मैचों में 55 से ज्यादा के औसत से रन बनाये थे। पाटीदार ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी सर्जरी की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, "अपने सभी समर्थकों से एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। मैंने हाल ही में एक चोट से उबरने के लिए सर्जरी करवाई है। यह चोट पिछले मुझे कुछ समय से परेशान कर रही थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जरी सही रही और मैं ठीक होने की राह पर हूँ।" उन्होंने कहा, "मैं मैदान पर फिर से उतरने और उस काम को करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जल्द वापसी करूंगा।" बीसीसीआई ने पाटीदार के रिहैबिलिटेशन का खर्च वहन करेगा।

महिला टी-20 मैच 4 गेंदों में खतम हुआ मैच, 9 रनों पर टीम ढेर

7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके



फिलीपींस (एजेंसी)। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा एक खेल है। कौन से मैच में क्या हो जाए...कहा नहीं जा सकता। अगर बल्लेबाज का दिन हो तो फिर गेंदबाजों की खे नहीं होती। वहीं गेंदबाजों का दिन हो तो फिर बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस जाते हैं। इन्हें से एक ऐसा ही पल सामने आता हुआ दिखा महिला इंटरनेशनल टी20 मैच में जहां, बल्लेबाजी करने वाली टीम पूरी तरह से तहस-नहस हो गई और विपक्षी टीम ने महज 4 गेंदों में ही मैच अपने नाम कर लिया।

दरअसल, एसीए गेम्स बुमिंग टी20 क्रिकेट कंपटीशन 2023 का दूसरा मैच थाइलैंड और फिलीपींस के बीच देखने को मिला। इस दौरान पहले बैटिंग करने उतरी फिलीपींस की टीम ने 11.1 ओवर तक सिर्फ 9 रन बनाए। जवाब में दूसरी टीम ने सिर्फ 4 गेंदों में बिना किसी विकेट के नुकसान के 10 रन बनाते हुए 10 विकेट से जीत दर्ज की। फिलीपींस की ओर से कोई भी बल्लेबाज चढ़ाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। टीम की ओर से 4 बल्लेबाजों ने 2-2 रन बनाए, जबकि एक रन अतिरिक्त रहा। इस तरह से कुल 9 रन बना। थाइलैंड के लिए थिफाना पुथवोंग ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, जबकि ओनिचा कामचोम्फू को 3 विकेट हासिल हुए। उनके अलावा, एक विकेट नट्टया बूचथम ने लिया।

पीटी उषा ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात कर समर्थन का आश्वासन दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के प्रति असवेदनशील होने के आरोपों का सामना कर रही भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार को जंतर-मंतर पर उनसे मुलाकात की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। पूर्व फर्टाटा धाविका उषा ने इससे पहले अपने मुद्दों के लिए आईओए से संपर्क करने के बजाय फिर से विरोध शुरू करने के लिए पहलवानों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहलवानों को अनुशासन दिखाना चाहिए था। इस टिप्पणी के बाद उनकी और आईओए की आलोचना हुई थी। उषा मीडिया से बात किए बिना चली गईं लेकिन बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है।



लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि वह पहले एथलीट हैं और बाद में प्रशासक हैं। तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले इस पहलवान ने कहा, "हमने उससे कहा कि हमें न्याय चाहिए। हमारा सरकार का विपक्ष या किसी और से कोई झगड़ा नहीं है। हम यहां कुश्ती की बेहतरी के लिए बैठे हैं। अगर यह मसला सुलझ जाता है और आरोप

(डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ) साबित हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग से जब पूछा गया कि क्या उषा सरकार या आईओए की ओर से समाधान लेकर आई थी तो उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह हमारे साथ हैं। बजरंग ने फिर से दोहराया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "अगर वह हमें आश्वासन दे रही हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें उस आश्वासन को पुरा करना चाहिए। लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट किया कि जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा, यह विरोध जारी रहेगा। हमें हालांकि न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जज उन्होंने कहा, "उन्होंने जो बातें कही हैं अगर उस दिशा में कोई पहल होती है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि वह हमारी सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगी। वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है।

मैड्रिड ओपन : दानिल मेदवेदेव उलटफेर का शिकार, खाचानोव जीते रियल मैड्रिड से भिड़ेगी भारतीय अंडर-17 टीम, कोच मैड्रिड

मैड्रिड (एजेंसी)। दानिल मेदवेदेव को मैड्रिड ओपन के चौथे दौर में झालीफायर अस्तान कारात्सेव के हाथों अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा जबकि स्टेफानोस सिसिपास और इगा स्विग्यातेक ने 3 सेट तक चले कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज करके अगले दौर में प्रवेश किया। 12 वीं रैंकिंग वाले कारात्सेव ने दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव को 7-6, 6-4 से मात दी। इस मैच से पहले दूर पर मेदवेदेव का रिकॉर्ड 33.4 का था। अब कारात्सेव का सामना टेलर फिट्ज या झांग झिंजेन से होगा। मेदवेदेव ने हम वतन रूसी खिलाड़ी एलेक्जेंडर शेवचेव को 4-6, 6-1, 7-5 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी।



गुजरने के बाद 31 वें वरीय सेबेस्टियन बेज को 7-5, 3-6, 6-3 से हराकर इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के अंतिम 16 में जगह बनाई।

महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी स्विग्यातेक को भी 16 वीं वरीयता प्राप्त एकातेरिना एलेक्जेंड्रोवा पर 6-4, 6-7 (3), 6-3 से जीत दर्ज करने के लिए पसीना बहाना पड़ा। उनका अगला मुकाबला 27 वीं वरीयता प्राप्त पेद्रा मार्टिच से होगा जिन्होंने 11 वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 7-6 (1) से हराया। मैड्रिड में पिछले साल की उपविजेता तीसरी वरीयता प्राप्त जेंसिका पेगुला ने मार्टिना ट्रैविंसन को 6-3, 2-6, 6-3 से

हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना स्क्लेका ने रूसी किशोरी मीरा एंड्रीवा को 6-3, 6-1 से पराजित करके उनके शानदार अभियान पर रोक लगाई। नौ वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी ने पाउला बडोसा को 6-4, 6-4 से, जबकि 12 वीं वरीयता प्राप्त वेरोनिका कुदरमेतोवा ने 8 वीं वरीयता प्राप्त डेरिया कसाटकाना को 7-5, 1-6, 7-6 (2) से हराया। पुरुष वर्ग के अन्य मैचों में 8 वीं वरीयता प्राप्त टेकर फिट्ज ने क्रिस्टियन गारिन को 6-1, 7-6 (4), झांग झिंजेन ने 11 वीं वरीयता प्राप्त कैमरून नॉरी को 2-6, 7-6 (2), 7-6 (2) और बर्नबे जपाटा मिरालेस ने झालीफायर रोमन स्फ्रीडलिन को 6-3, 3-6, 6-3 से पराजित किया।

हाराक अंतिम 8 में प्रवेश किया। दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना स्क्लेका ने रूसी किशोरी मीरा एंड्रीवा को 6-3, 6-1 से पराजित करके उनके शानदार अभियान पर रोक लगाई। नौ वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी ने पाउला बडोसा को 6-4, 6-4 से, जबकि 12 वीं वरीयता प्राप्त वेरोनिका कुदरमेतोवा ने 8 वीं वरीयता प्राप्त डेरिया कसाटकाना को 7-5, 1-6, 7-6 (2) से हराया। पुरुष वर्ग के अन्य मैचों में 8 वीं वरीयता प्राप्त टेकर फिट्ज ने क्रिस्टियन गारिन को 6-1, 7-6 (4), झांग झिंजेन ने 11 वीं वरीयता प्राप्त कैमरून नॉरी को 2-6, 7-6 (2), 7-6 (2) और बर्नबे जपाटा मिरालेस ने झालीफायर रोमन स्फ्रीडलिन को 6-3, 3-6, 6-3 से पराजित किया।

स्पेन (एजेंसी)। भारतीय अंडर-17 पुरुष फुटबॉल टीम बुधवार को यहां अभ्यास मैच में स्पेन के अग्रणी क्लब रियल मैड्रिड का अंडर-17 टीम से मुकाबला करेगी। भारतीय युवा वर्तमान में इस साल जून में थाइलैंड में आयोजित होने वाले एएफसी अंडर-17 एशियाई कप की कक्षा में एक रहे हैं जहां उन्हें जापान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के साथ रूपा-डी में रखा गया है। मुख्य कोच बिबियानो फर्नांडिस के नेतृत्व में भारतीय युवाओं ने एटलेटिको डी मैड्रिड अंडर-17 (4-1), सीडी लेगानेस अंडर-18 (0-2) और एटलेटिको मैड्रिलिनो (2-1) के खिलाफ

टीम इस प्रकार हैं

कोलकाता नाइट राइडर्स- नीतीश राणा (कप्तान), रहमानुल्लाह गुस्वा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, शार्दूल ठाकुर, लॉकी फर्ग्युसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, रिंकू सिंह, एन. जागदीश, वैभव अरोड़ा, सुशर शर्मा, डेविड विसी, कुलवंत खेंजरालिया, लिटन दास, मनदीप सिंह और जेसन रॉय।

सनराइजर्स हैदराबाद - एडेन मार्करम (कप्तान), अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, फुलानहक फारूकी, कार्लिन त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, उमरान मलिक, हेरी ब्लूक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन, आदिल राशिद, मयंक मारकंडे, विवरत शर्मा, समथ व्वास, संवीर सिंह, उषेंद्र यादव, मयंक झापर, नीतीश कुमार रेड्डी, अकील होसेन और अनमोलप्रीत सिंह।

मैच शुरू - भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे।



दिल्ली में नहीं उठाई जाएगी पार्क की गई ओवर एज गाड़ियां; सड़क पर होगा एक्शन, कैलाश गहलोत ने विभाग को लिखा पत्र

नई दिल्ली, एंजेंसी। दिल्ली की सड़कों पर ओवरएज हो चुके वाहनों को उठाने के फैसले पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रोक लगाने का फैसला किया है। परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया कि उनको खबर मिली है कि मंत्री ने इस फैसले पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन उन्हें अभी पत्र मिला नहीं है। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने पार्क की गई ओवरएज गाड़ियों को उठाने का फैसला किया था। ओवर एज गाड़ियों को पार्किंग से उठाने के फैसले पर रोक की खबर के बाद विभाग का बयान आया है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि ओवर एज गाड़ियों पर कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि नियम के अनुसार, ऐसी गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं है।



उठा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पार्क की गई ओवर एज गाड़ियों को उठाने के फैसले पर रोक के बावजूद सड़क पर चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कई लोगों द्वारा

अनिवार्य नहीं है। विभाग के पास दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन पार्क किए गए वाहन को जबरन खींचकर ले जाने की अनुमति नहीं है और इसे तुरंत बंद करने की जरूरत है। हाल ही में एक बैठक में, मंत्री ने

विशेष आयुक्त (प्रवर्तन) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जब परिवहन आयुक्त छुट्टी पर थे, और विशेष आयुक्त को निर्देशित किया गया था कि पार्क किए गए वाहनों को दूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह न केवल अवैध है बल्कि अवैध है साथ ही शहर में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। मंत्री के पास खड़े वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ विभिन्न लोगों ने मंत्री के पास पहुंचकर राहत की मांग की है।

इस मामले को लेकर एक मीटिंग में मंत्री गहलोत ने प्रवर्तन के विशेष आयुक्त से चर्चा की थी। परिवहन आयुक्त उस समय छुट्टी पर चल रहे थे। इस दौरान मंत्री गहलोत के पास लोगों ने खड़े वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में मंत्री ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद विशेष आयुक्त (प्रवर्तन) अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पर रख सकता हूँ कि ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद, जहां परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा एक वाहन को पार्क की स्थिति में ले जाया गया है, संबंधित अधिकारी अपना बचाव खुद कराया, सरकार उसका बचाव नहीं करेगी।

जून में खुलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा सेवशन, दिल्ली-गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली, एंजेंसी। हरियाणा सरकार में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को गुरुग्राम के लघु सचिवालय के कार्यक्रम हॉल में विभिन्न सरकारी विभागों की बड़ी परियोजनाओं, मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि जून माह में द्वारका एक्सप्रेस-वे का हरियाणा सेक्शन ट्रेफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ट्रेफिक के दबाव को कम करने व दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी के लिए विकसित किया जा रहा द्वारका एक्सप्रेस-वे वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (स्वर्णिम चतुर्भुज की दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई शाखा का हिस्सा) और मुख्य रूप से पश्चिम दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कों पर दबाव कम करेगा। उन्होंने कहा कि एनएच आठ पर पचास से साठ प्रतिशत ट्रेफिक को नए एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा, जिससे सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड और एयर



एक्सप्रेसवे की ओर यातायात में सुधार होगा। वर्ष 2023 में इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

नोएडा में मिला यीस्ट संक्रमित दुनिया का पहला मरीज

नई दिल्ली, एंजेंसी। शहर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को रोडेटुरुला संक्रमण और सीएमवी मेनिंगजाइटिस से पीड़ित दुनिया का पहला मरीज मिलने का दावा किया है। यीस्ट के संक्रमण से जुड़ी यह बीमारी एक नवजात में पाई गई। इलाज के बाद यह बच्चा अब स्वस्थ है। फोर्टिस अस्पताल के शिशु रोग विभाग के प्रमुख डॉ. आशुतोष सिन्हा ने बताया कि 19 जनवरी को परिजन दो माह के एक बच्चे का इलाज कराने के लिए अस्पताल आए थे। वो मधुरा के रहने वाले हैं। नवजात में बुखार, चिड़चिड़ापन, शरीर में असामान्य हकटत जैसी परेशानियां दिखीं। उसे रोज तीन से चार बार बुखार आ रहा था। एमआरआई, सीएसएफ (सेरीब्रोस्पॉन्ड्रल फ्लूइड), बायोफायर समेत कई प्रकार की मेडिकल जांच की गई, जिसमें दुर्लभ संक्रमण के बारे में पता चला।

संजय सिंह का दावा- शराब घोटाले में नाम जोड़ने पर ईडी ने जताया खेद

नई दिल्ली, एंजेंसी। शराब घोटाले की चार्जशीट में प्रवर्तन निदेशालय से एक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नाम जोड़ने का दावा किया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में उन्हें चिट्ठी लिख कर अपना खेद जताया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वित्त सचिव को एक खत लिखा था और कहा था कि उन्हें ईडी के डायरेक्टर और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंजल से जांच कर रही है।

इससे पहले संजय सिंह ने एक खत टवीट किया था और कहा था कि उन्होंने ईडी के निदेशक और एक अन्य अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर वित्त सचिव को खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि चार्जशीट में मेरा नाम जानबूझ कर मेरी छवि खराब करने के लिए लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान दिनेश अरोड़ा के एक बयान का जिक्र किया गया है जिसमें वो कहता है, अमित ने उनसे मदद मांगी थी कि उसकी दुकान को पीतम्पुरा से ओखला शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि यह मामला आबकारी विभाग के पास पेंडिंग था। इसी तरह उसने यह मुद्दा संजय सिंह के निर्देश पर मनीष रिसेादिया के सामने उठाया था। बाद में आबकारी विभाग ने इस मामले का निपटारा कर दिया था। इससे पहले संजय सिंह यह कह चुके हैं कि उन्होंने संसद में कई बार जांच एंजेंसियों का जिक्र अपने भाषण में किया है इसी वजह से इस साल छह जनवरी को ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आया था।

अब दिल्ली में भर्ती घोटाला, प्रोफेसरों की नियुक्ति में बड़ी धांधली का खुलासा; एलजी ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली, एंजेंसी। उ्प राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) की भर्ती में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें आई थीं। राजनिवास के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उ्प राज्यपाल ने डीपीआरएसयू में फैकल्टी सदस्यों के पदों पर हुई नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में फैकल्टी स्टाफ की जो नियुक्तियां हुई थीं, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाला, पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है। जानकारी के अनुसार, इस संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फरवरी और जुलाई 2019 में आवेदन निकाले गए थे। इसके कुछ ही महीने बाद 2020 में इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतें मीडिया में आने लगी थीं। शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने डीपीआरएसयू से रिकॉर्ड मांगा और उसके आधार पर विभाग की सकारता शाखा ने उन छह उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित कागजात की जांच की। इस जांच में कई अनियमितताएं मिलीं।

पाकिस्तान में अप्रैल में आतंकी हमलों में हुई मामूली वृद्धि



इस्लामाबाद, एंजेंसी। पाकिस्तान में अप्रैल में कुल 48 घटनाओं के साथ आतंकवादी हमलों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई, जिसमें 68 मौतें हुईं और 55 घायल हुए। एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। समाचार एंजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जारी रिपोर्ट में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज ने कहा कि नए आंकड़े मार्च में दर्ज किए गए 39 आतंकवादी हमलों से अधिक हैं, जिसमें 58 मौतें

और 73 घायल हुए थे। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक ने कहा कि आंकड़ों में आतंकवादी हमलों में 23 फीसदी की वृद्धि, मौतों में 17 फीसदी की बढ़ोतरी और घायल लोगों की संख्या में 25 फीसदी की कमी देखी गई है।

41 आतंकवादियों को मार गिराया और 40 को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा पिछले महीने हुए कुल हमलों में से 49 फीसदी के साथ सबसे अधिक प्रभावित प्रांत रहा। पिछले हफ्ते, सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने घोषणा की थी कि इस साल जनवरी से अब तक पाकिस्तान में 436 आतंकवादी हमलों में कुल 293 लोग मारे गए हैं और 521 अन्य घायल हुए हैं।

पाकिस्तान में कपूर हवेली पर मालिकाना हक वाली याचिका खारिज

कोर्ट ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाजत नहीं दी, यहीं राज कपूर का जन्म हुआ था

पेशावर एंजेंसी। पाकिस्तान की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। पेशावर के सईद मुहम्मद की दलील थी कि उनके पिता ने 1969 में नीलामी के जरिए यह हवेली खरीदी थी। तब से वे ही इसके मालिक हैं। लिहाजा इसका मालिकाना हक उन्हें दिया जाए। याचिका लगाने वाले सईद के वकील खताक ने कोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तान के किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि राज कपूर या उनका परिवार कभी इस हवेली में रहा था। हालांकि, कोर्ट ने फिर भी मामला सिविल कोर्ट में ले जाने की बात कही। **हवेली की जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं इसके मालिक:** राज कपूर की इस हवेली को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। इसे खरीदने वाले सईद

मुहम्मद हवेली को तोड़कर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। **2014 में नवाज सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था:** कोर्ट ने ये फैसला दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हवेली पर कब्जे से जुड़े एक आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनाया। दिलीप कुमार की ये हवेली पेशावर के लोकप्रिय किस्सा खानी बाजार में स्थित है। इस हवेली को नवाज शरीफ की सरकार 2016 में ही राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुकी है। **जज ने पूछा- क्या कभी इस हवेली में रहे राज कपूर?:** इस पर जस्टिस शकर ने आफिथोर्स की विभाग से पूछा कि क्या उनके पास कोई दस्तावेज या सबूत हैं, जिससे पता चल सके कि राज कपूर का परिवार कभी इस हवेली में रहा था? वकील खताक ने दावा किया कि किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके

कि राज कपूर या उनका परिवार कभी इस हवेली में रहा था। हालांकि, जजों की बेंच ने फिर भी मामला सिविल कोर्ट में ले जाने की बात कही। **2005 के भूकंप के बाद जर्जर हुई थी हालत:** राज कपूर की ये हवेली अब बहुत ही जर्जर हालत में है। 40 से 50 कمرों वाली शानदार पांच मंजिला इमारत का टॉप और चौथा फ्लोर ढह चुका है। इसके मौजूदा मालिक इस हवेली को ढहकर यहाँ एक कॉमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं। हालांकि, ऑर्थोडॉक्स विभाग इसके खिलाफ है। वो इस हवेली के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस धरोहर को सहेजकर रखना चाहता है। राज कपूर की हवेली के बारे में मशहूर है कि 1947 में पार्टीशन से पहले शादी की पार्टी देने के लिए लोगों की पहली पसंद होती थी। हवेली में बुकिंग नहीं मिलने के चलते 6-6 महीने डेट्स आगे बढ़नी पड़ती थीं। लेकिन भूकंप के बाद



इसकी हालत खराब होती गई। 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन घरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था पर इसे संरक्षित करने के लिए कोई इशारे तक नहीं पहुंचा था।

100 साल पुरानी है कपूर हवेली: यह हवेली पृथ्वीराज कपूर के पिता और ऋषि कपूर के परदादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने 1918-1922 के बीच बनवाई थी। हवेली के बाहर लगी लकड़ी की प्लेट के मुताबिक, बिल्डिंग का बनना 1918 में शुरू हुआ और 1921 में यह तैयार हो गई। इस हवेली में 40-50 कमरे हैं और हवेली के बाहरी हिस्से में खूबसूरत मोटिफ उमरे हुए हैं। इसमें आलीशान झरोखे बने हुए हैं। इसी हवेली में राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म हुआ था। 1990 में ऋषि कपूर और रणधीर कपूर हवेली देखने पहुंचे थे।

दिलीप कुमार की पुरानी हवेली भी कपूर हवेली के पास ही है। दोनों हवेलियों के मालिकों ने कई बार इन्हें गिराकर कॉमर्शियल प्लाजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी।